शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 234 | गुवाहाटी | गुरुवार, 27 मार्च, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

नक्सली संगठन नाबालिगों को दे रहे गुरिल्ला वार व बम बनाने की ट्रेनिंग पेज 2
आरएसएस ने की बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता की अपील पेज 3
राजस्थान का किसान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आदर्श... पेज 5
फिल सिमंस 2027 वनडे विश्व कप तक बने रहेंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पेज 7

हाई स्कूल पेपर लीक मामला

पुलिस हिरासत में रहेगा प्रश्नपत्र परीक्षा के दिन भेजा जाएगा केंद्र

गुवाहाटी। हाल ही में उच्चतर माध्यमिक (एचएस) प्रथम वर्ष की परीक्षा के पेपर लीक होने के मद्देनजर, असम शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित करने और भविष्य में गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने बुधवार को घोषणा की कि आगे चलकर, एचएस परीक्षा के प्रश्नपत्रों को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाने से पहले केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया जाएगा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रश्न-पत्र स्थानीय पुलिस थानों में रखे जाएंगे तथा परीक्षा के दिन स्कूलों में पहुंचा दिए जाएंगे। पेगू ने कहा कि इन कदमों से पेपर लीक के कारण होने वाली असुविधा और अराजकता पर लगाम लगेगी। हमारा उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना और छात्रों की मेहनत की रक्षा करना है। 21 मार्च, 2025 को लीक की सूचना मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और पेपर की सुरक्षा सील तोड़ने के लिए 18 निजी स्कूलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कक्षा 11 की परीक्षाएं, जो दो वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, केंद्रीयकृत परीक्षा केंद्रों के बिना, -शेष पृष्ठ दो पर

मुख्यमंत्री ने राज्य के एनडीए सांसदों संग बैठक की, विकास के लिए मांगे सुझाव

नई दिल्ली। असम भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी सत्ता बचाए रखने की कोशिश में जुट गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज राज्य के एनडीए सांसदों से मुलाकात की। शर्मा ने सांसदों से राज्य के लिए काम को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। मुलाकात के दौरान सीएम शर्मा ने राज्य से संबंधित अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की और संसद में प्रासंगिक मुद्दों को उठाने के लिए उनकी सराहना भी की। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को बुलाई गई बैठक -शेष पृष्ठ दो पर

मातृ वंदन योजना रास में सोनिया ने सरकार को घेरा

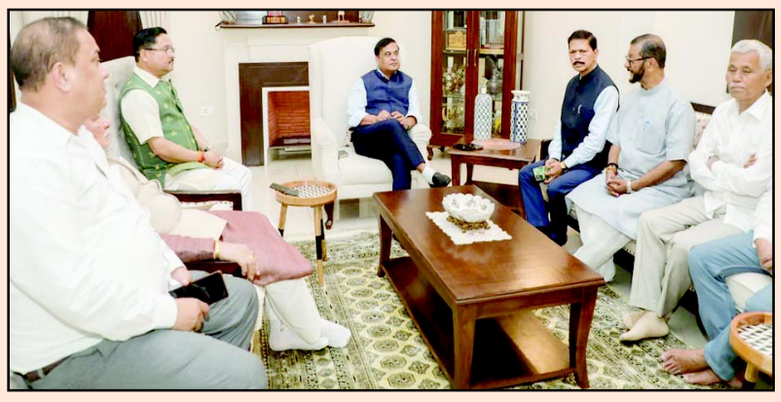

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान गरीब गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाले मातृ वंदन योजना के तहत निर्धारित राशि नहीं मुहैया कराने का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए प्रति बच्चा पोषण के लिए देने का भी प्रावधान है। सोनिया गांधी ने कहा कि योजना 2017 में शुरू हुई थी, जो इस प्रावधान को ही पूरा करने के लिए थी लेकिन इस योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर केवल पांच हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो यही लाभ दिया जा रहा है। साल 2022-23 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक 68 फीसदी -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए

इंफाल। भारतीय सेना और असम राइफल्स की फॉर्मेशन ने स्पीयर कोर के तहत पिछले तीन दिनों में मणिपुर के ककचिंग, इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, सेनापति और बिष्णुपुर जिलों में खुफिया सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन चलाए। ये ऑपरेशन मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के समन्वय से चलाए गए थे। समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप 32 हथियारों, गोला-बारूद और अन्य युद्ध जैसे भंडार -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे कर रही है काम : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य प्रशासन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जानवरों के आवास का विस्तार हो रहा है। अपने एक्स हैंडल पर सीएम शर्मा ने लिखा कि जीवों के आवासों का विस्तार किया जा रहा है। नियमित गश्त के दौरान, विश्वनाथ पुलिस ने विश्वनाथ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 6वें विस्तार में एक बाघ को देखा। हम अपने जीव-जंतुओं के लिए उपयुक्त आवास बना रहे हैं और चौबीसों घंटे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं ताकि वे फलते-फूलते रहें। मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले उल्लेख किया था कि असम में हात्र के वर्षों में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पिछले चार वर्षों में तीन करोड़ से अधिक घरेलू पर्यटक राज्य मैं आए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि भारत में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

बहुत-सी तथा बड़ी गलतियां किए बिना कोई आदमी बड़ा और महान नहीं बनता।

-ग्लेडस्टन

पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन

गुवाहाटी। वरिष्ठ पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की कथित राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी के विरोध में गुवाहाटी में पत्रकार समुदाय बुधवार को सड़कों पर उतर आया। शहर स्थित समाचार पोर्टल द *क्रॉसकरंट* के रिपोर्टर और गुवाहाटी प्रेस क्लब के सहायक महासचिव मजूमदार को उसी दिन अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगी। पत्रकार, संपादक, कार्यकर्ता और छात्र समूह अम्बारी में गुवाहाटी प्रेस क्लब के बाहर एकत्र हुए और गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने वाली आवाजों को डराने का प्रयास बताया। प्रदर्शनकारी पत्रकारों में से एक ने कहा कि यह सिर्फ दिलवर -शेष पृष्ठ दो पर

ईसी ने पहली बार एक लाख से अधिक बीएलओ के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया

दो दिवसीय कार्यक्रम में असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का पहला बैच लेंगे भाग

गुवाहाटी /नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बीएलओ के पहली बार हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगले कुछ वर्षों में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में औसतन 10 मतदान केंद्रों पर एक बीएलओ को शामिल करते हुए एक लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये सुप्रशिक्षित बीएलओ

जो 100 करोड़ निर्वाचकों और आयोग के बीच पहले और सबसे महत्वपूर्ण इंटरफेस होते हैं, विधान सभा स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों (एएलएमटी) के एक ऐसे कोर (00199) का निर्माण करेंगे जिससे देश भर में बीएलओ का संपूर्ण नेटवर्क मजबूत बनेगा। यह अद्वितीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में जारी रहेगा, जिसमें पहले चरण में चुनाव होने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

बिहार विस में उठी लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग

पटना (हि.स.)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग से जुड़े प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। विधानसभा में राजद ने लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। राजद के मुकेश रौशन बुधवार को -शेष पृष्ठ दो पर

द. कोरिया में भीषण आग से अब तक 18 लोगों की मौत

सियोल। दक्षिण कोरिया में दक्षिणी इलाकों के जंगलों में आग लगने से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, आग को बुझाने के प्रयासों के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोरिया वन सेवा ने बुधवार को कहा कि बचाव प्रयास जारी हैं और ऐसा अनुमान है कि विमान में केवल एक पायलट था। अग्निशमन दल दक्षिण कोरिया के दक्षिणी इलाकों में लगी भीषण आग को बुझाने के काम में -शेष पृष्ठ दो पर

दुष्कर्म पर इलाहाबाद एचसी की टिप्पणी पर भड़का एससी, फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली। दुष्कर्म मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जजों ने फैसले को असंवेदनशील और अमानवीय बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि *नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप नहीं।* अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि हमें ये देखकर दुख हो रहा है कि फैसला लिखने वालों में संवेदनशीलता नहीं है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बुधवार को सुनवाई की। -शेष पृष्ठ दो पर

दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी खिलेगा कमल : अमित शाह

नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी कमल खिल गया है। दिल्ली बच गई थी, लेकिन अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी आ चुका है। अपने बयान में आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर इशारा करते हुए कहा कि अब केवल पश्चिम बंगाल बचा है, और चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में भी आएगा। दिल्ली और पश्चिम बंगाल पर बोलने के बाद अमिक शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर अपना बयान दिया। उन्होंने लोकसभा में इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता का क्षेत्र देश के हर परिवार को जोड़ता है। उन्होंने बताया कि हर गांव में कोई न कोई सहकारी संस्था होती है, जो कृषि, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार से जुड़ी होती है और देश की प्रगति में योगदान -शेष पृष्ठ दो पर

लोस अध्यक्ष ने राहुल गांधी को दी मर्यादित आचरण करने की नसीहत

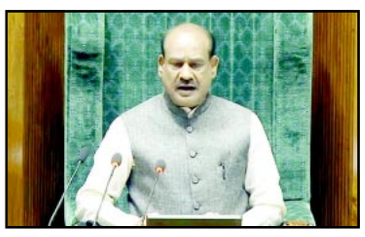

नई दिल्ली (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आचरण संबंधी मर्यादाओं के पालन करने की नसीहत दी। शून्यकाल की समाप्ति के पूर्व उन्होंने सदन की नियम प्रक्रिया के तहत मर्यादा और आचरण करने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदडों को बनाए रखना चाहिए। सदन में उनके संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं, जब सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप नहीं रहे हैं। इस सदन में पिता-पुत्र मां-बेटी -शेष पृष्ठ दो पर

जीत गए नेतन्याहू?

उत्तरी गाजा में हमास बाहर जाओ के लगे नारे, फिलिस्तीनी नागरिकों ने निकाली रैली

गाजा पट्टी। इजरायल और हमास के बीच की जंग को यूं तो डेढ़ बरस गुजर चुके हैं। 7 अक्तूबर 2023 को शुरू हुए इस युद्ध में इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन गाजा में अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अब ये जरूर कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे इस जंग की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। दरअसल, नेतन्याहू हमेशा से कहते आए हैं कि वो फिलिस्तिनियों के विरोधी

नहीं हैं। लेकिन हमास को गाजा से निकालना चाहते हैं। ये उनकी लड़ाई है। वहीं अब गाजा में हमास के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने उत्तरी गाजा की सड़कों पर हमास के शासन को समाप्त करने और इजरायल के साथ युद्ध को समाप्त करने की मांग की। एएफपी के अनुसार, यह प्रदर्शन कथित तौर पर इजरायल के साथ संघर्ष के फिर से शुरू -शेष पृष्ठ दो पर

बीएलए के आगे बेबस हुआ पाकिस्तान

अब जिनपिंग ने सीपीईसी के लिए अपने सुरक्षा बल किए तैनात

इस्लामाबाद /बीजिंग। चीन ने पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच अपनी परियोजनाओं और देशों की सुरक्षा के लिए पहली बार पाकिस्तान में निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान में विभिन्न चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजनाओं में शामिल अपने इंजीनियरों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह घटनाक्रम बलूच आतंकवादियों द्वारा एक पाकिस्तानी सैन्य बस को उड़ाए जाने और कम से कम 90 सैनिकों को मारने का दावा करने के कुछ दिनों बाद हुआ है। कुछ दिन पहले, आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और 214 सैन्य बंधकों को मारने का दावा किया था। चीन ने संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

नक्सली संगठन नाबालिगों को दे रहे गुरिल्ला वार व बम बनाने की ट्रेनिंग

मारे गए इनामी नक्सली से बरामद पत्र में हुआ खुलासा

जगदलपुर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली संगठन नाबालिग बच्चे-बच्चियों के हाथों में हथियार पकड़ा रहे हैं। साथ ही जंगल में इनको बम बनाना सिखाने व गुरिल्ला वार की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका खुलासा दंतेवाड़ा-बीजापुर जिले की सीमा पर मंगलवार को हुए मुठभेड़ में मारे गए 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर के पास से बरामद चार पन्नों के पत्र से हुआ है। पत्र में मिले सबूत के अनुसार जंगल में नाबालिक बच्चों को हथियार चलाना (स्नाइपर चलाना) और आईईडी बनाना भी सिखा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नक्सली लीडर सुधाकर उर्फ मुरली के पास से पुलिस ने सामान के साथ तेलुगु भाषा में लिखा एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसमें नक्सल संगठन में नए लड़कों की भर्ती और नक्सली लीडर्स के साथ बैठक सहित कई बातें लिखी हुई हैं। पत्र में लिखा है कि कुछ दिन पहले नक्सलियों की उत्तर बस्तर ब्यूरो में माड़ इलाके में सीसीएम, डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सलियों की हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में नक्सल संगठन के काम, नुकसान, कामयाबी और चुनौतियों की समीक्षा की गई, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका उल्लेख पत्र में किया गया है। पत्र में लिखा है कि जिन लड़कों की भर्ती की गई है, वे अभी लड़ने योग्य नहीं हैं। नक्सल संगठन को लड़ाके चाहिए, जो भर्ती हुए हैं, उन्हें नक्सल नीति, राजनीति, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। उनको अभी लड़ने योग्य बनाने में समय लगेगा। जो संगठन में हैं, उनमें ज्यादातर लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ मारे गए हैं। अगर नक्सल संगठन में नई भर्तियां नहीं होती हैं तो नक्सलवाद का अस्तित्व खतरे में है। पत्र को अलग-अलग एरिया कमेटी में भेजकर उन्हें नई भर्ती और मीटिंग में हुई समीक्षा की जानकारी दी गई है। नक्सलियों के चार पन्नों के तेलुगु भाषा में हाथ से लिखे पत्र में पूरा लेखा-जोखा है। लिखा है कि माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया कमेटी और नेलनार एरिया में 130 लोगों की नई भर्ती हुई है, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिए हैं। 18 से 22 उम्र के युवक-युवतियों को हथियार थमाया गया है, लेकिन 9 से 17 उम्र तक के अभी बच्चे हैं।

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट हर बार की तरह पक्षपाती : भारत

नई दिल्ली (हि.स.)। भारत ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हर बार की तरह पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित आकलन जारी किया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें लगता है कि यूएससीआईआरएफ को ही चिंता की एक इकाई के रूप में नामित कर देना चाहिए। भारत ने कहा कि यूएससीआईआरएफ के लगातार कुछ घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत के जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज पर आकांक्षा जताने के प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता पर वास्तविक चिंता के बजाय जानबूझकर चलाया जा रहा एजेंडा दिखाई देता है।

ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर गुवाहाटी में नए अंदाज में किया प्रस्तुत

गुवाहाटी। ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर ने गुवाहाटी में एक यादगार शोकेस के साथ इस एडिशन का भव्य समापन किया, जहां शहर को उच्च फैशन के रंग में रंग दिया गया। अपने अनोखे *प्ले एन-वोग* कांसेप्ट के तहत टूर ने एट-लीजर स्टाइल को नए और आधुनिक अंदाज में पेश किया। यह भव्य आयोजन गुवाहाटी के खूबसूरत और वाइब्रंट ग्रीनवुड रिजॉर्ट में हुआ, जहां डिजाइनर नितिन बाल चौहान, नॉटवन के अभिषेक पाटनी और पवन सचदेवा ने अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल कलेक्शन प्रस्तुत किए। शो का आकर्षण रहे करिश्माई शोस्टॉपर ईशान खट्टर, जिन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति से रैंप पर चार चांद लगा दिए। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया (एफडीसीआई) के सहयोग से, ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर ने भारत के फैशन जगत को एक नया आयाम दिया, जहां नवोन्मेषी शोकेस प्रस्तुत किए गए। इस साझेदारी ने गुवाहाटी में अपनी बुलंदियों को छुआ, नए मानक स्थापित किए और टूर को इंडस्ट्री का ट्रेंडसेटर बनने का दर्जा दिलाया। डिजाइनरों ने एट-लीजर को एक नए अंदाज में पेश किया, जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सिलुएट्स, चमकदार रंगों और स्टेटमेंट पीसेस का उपयोग किया। उनके कलेक्शन में ओवरसाइज़्ड फिट्स, असिमेट्रिकल कट्स और बोल्ड ग्राफिक्स शामिल थे, जो स्टाइल और आराम का अनोखा मेल प्रस्तुत करते हैं। अभिषेक पाटनी के ब्रांड नॉटवन का *रेसर 01* कलेक्शन स्ट्रीटवियर और रॉकस्टार स्टाइल का अनोखा मिश्रण था। यह म्यूजिक से प्रेरित बोल्ड और नोस्टैल्जिक पीसेस के जरिए फैशन को नए अंदाज में प्रस्तुत करता है।

भारी मात्रा में गांजा समेत एक तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की दिसपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चला कर भारी मात्रा में गांजा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि राजधानी के कहिलीपाड़ा इलाके के नरकासुर पहाड़ इलाके में चलाए गए अभियान के दौरान 50.456 ग्राम गांजा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शांतनू कर (29) के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से नगद 11, 150 रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस इस संबंध में एनडीपीएस की धारा के तहत एक प्राथमिककी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी से सघन पूछताछ कर रही है।

बिहाली में नुक्कड़ नाटक का मंचन

बिश्वनाथ (हिंस)। बिहाली के बोरगांग वन अधिकारी की पहल पर और तेलेंगनिया गांव के छात्र-छात्राओं द्वारा बेदेतिर साप्ताहिक बाजार और बोरगांग सेंटर में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य-हाथी और मानव संघर्ष को रोकना, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, पेड़ों की कटाई को रोककर पर्यावरण की रक्षा करना आदि था।

कोकराझाड़ में आसू की नशा विरोधी जागरूकता रैली आयोजित

कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ में आज आलम असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की ओर से नशा विरोधी जागरूकता रैली आयोजित की गई। आसू, असम उन्नति सभा और असम सेना के आह्वान पर बुधवार को कोकराझाड़ जिला शहर में नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली कोकराझाड़ जिला आसू के मुख्य कार्यालय से शुरू की गई। इस कार्यक्रम में आसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष नवज्योति राय ने भी भाग लिया। रैली के दौरान लोगों को नशा से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत किया गया। रैली में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार

कोकराझाड़ (हिंस)। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, असम की टीम ने आज कोकराझाड़ जिले के फकीराग्राम नगर पालिका बोर्ड के जूनियर इंजीनियर नेकिबुज जामान को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जामान पर आरोप है कि वह एक दुकान के नवीनीकरण की अनुमति देने के बदले में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी।

पृष्ठ एक का शेष

पुलिस हिरासत में ...

अलग-अलग स्कूलों द्वारा आयोजित की जाती हैं। पेगू ने कहा कि हालांकि ये परीक्षाएं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का निर्धारण नहीं करतीं, लेकिन वे छात्रों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे पहले, सुचारू प्रशासन के लिए प्रश्न-पत्र काफी पहले ही स्कूलों को भेज दिए जाते थे, तथा निर्देश दिए जाते थे कि सीलबंद पैकेट केवल परीक्षा के दिन ही खोले जाएं। हालांकि, स्कूल अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश के कारण प्रश्नपत्र लीक हो गए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया बाधित हुई। कक्षा 11वीं के गणित के पेपर लीक होने के कारण काफी विरोध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 15 निजी स्कूलों की संबद्धता निलंबित कर दी गई। असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) ने भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिणामस्वरूप, 24 से 29 मार्च तक निर्धारित कक्षा 11 की सभी परीक्षाएं, जिनमें 36 विषय शामिल थे, रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों छात्र प्रभावित हुए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के...

में, मुख्यमंत्री ने एनडीए सांसदों के साथ असम में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में विकास की गति को और तेज करने के लिए अपनी ऊर्जा को कैसे चैनलाइज किया जाए, इस पर भी विस्तार से मंथन किया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने के अलावा सांसदों से राज्य में विकास कार्य को लेकर फीडबैक भी लिया। जारी बयान में यह भी कहा गया कि सांसदों से जनता के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर भी सुझाव मांगे गए। बैठक के बाद सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली में असम के प्रतिष्ठित एनडीए सांसदों के साथ एक शानदार बैठक हुई। वे राष्ट्रीय राजधानी में हमारे लोगों के मुद्दों को उठाने में सराहनीय काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस बात पर भी गंभीर चर्चा की कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में असम की प्रगति को गति देने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को कैसे बेहतर ढंग से समन्वित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सरकार के साथ बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में दिलीप सैकिया, कामाख्या प्रसाद तासा, भुवनेश्वर कलिता, प्रदान बरुआ, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और पबित्र मार्गेरिटा हैं।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ...

की बरामदगी हुई। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कोहिमा में बताया कि पिछले शनिवार को ककचिंग जिले के मोलटिनचैन में, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इसमें एक इम्प्रवाइज्ड मोर्टार, एक 0.303 राइफल, एक संशोधित कार्बाइन मशीन गन, दो सिंगल बैरल राइफल गोला-बारूद और युद्ध जैसे भंडार बरामद किए। वहीं, सेनापति जिले के हेंबंग में चार बोल्ट एक्शन राइफल्स बरामद की गईं। इंफाल पूर्व जिले के सगोलमंग से दो सिंगल बोर बैरल राइफल्स और दो इम्प्रवाइज्ड मोर्टार, गोला-बारूद और युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए। प्रवक्ता ने बताया कि रविवार को भी भारतीय सेना ने सेनापति जिले के फाइकोट में ऑपरेशन चलाया। यहां से एक इनसास, एक .303 राइफल और एक सेल्फ लोडिंग राइफल (एसएलआर) बरामद की। वहीं, असम राइफल्स ने इंफाल पूर्व से एक 2 मोर्टार और एक 0.32 मिमी पिस्टल बरामद की। इसी तरह से मंगलवार को सेना ने इंफाल पूर्व नें तलाशी अभियान चलाया। यहां से एक 0.22 राइफल, एक 12 बोर डबल बैरल राइफल, चार 51 मिमी मोर्टार और एक 9 मिमी पिस्टल बरामद की। इसी दिन सेना ने बिष्णुपुर जिले के डंपि से एक एक-47, एक 12 बोर राइफल, एक .303 राइफल, एक डबल बैरल राइफल, एक संशोधित राइफल और दो इम्प्रवाइज्ड मोर्टार बरामद किए। प्रवक्ता ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं को मणिपुर पुलिस को आगे की जांच और वितरण के लिए सौंप दिया गया है।

पत्रकार की गिरफ्तारी...

हुसैन पर हमला नहीं है, बल्कि सभी पत्रकारों और स्वतंत्र प्रेस के लिए खतरा है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य पुलिस और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाते हुए पान बाजार पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करने से पहले एक मानव श्रृंखला बनाई। जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो एक छोटी सी झड़प हुई। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (एएएसयू) की साहित्यिक सचिव निहारिका शॉ इकिया ने कहा कि सरकार सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहती है। अगर पत्रकार इसकी कमियों को उजागर नहीं करेंगे, तो और कौन करेगा? इस राजनीतिक रूप से प्रेरित कृत्य का उद्देश्य अधिकारियों से सवाल करने वालों को चुप कराना है। विरोध प्रदर्शन केवल गुवाहाटी तक सीमित नहीं रहा। जोरहाट, डिब्रूगढ़ और विश्वनाथ में भी पत्रकारों ने मजूमदार की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जोरहाट में प्रेस क्लब के सचिव परमानंद बोरा ने पत्रकारों के प्रति बढ़ती दुश्मनी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र माहौल के बजाय, हम प्रेस के प्रति दमनकारी रवैया देखते हैं। मजूमदार को 25 मार्च को असम सहकारी शीर्ष बैंक के प्रबंध निदेशक डंबरू सैकिया से करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले के आरोपों के बारे में पूछताछ करने का प्रयास करने के बाद हिरासत में लिया गया था। वह पान बाजार में बैंक परिसर के बाहर असम जातीय परिषद (एजेपी) की युवा शाखा जातीय युवा शक्ति द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। क्रॉसकरंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में मजूमदार को सैकिया से सवाल करते हुए दिखाया गया, जिन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने कार्यालय में चर्चा जारी रखें। कुछ ही क्षणों बाद, मजूमदार को पान बाजार पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्हें लगभग 12 घंटे तक हिरासत में रखा गया। क्रॉसकरंट के संपादक अरूप कलिता ने हिरासत की निंदा की। उन्होंने कहा कि हमें मजूमदार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस ने उनके खिलाफ लगाए गए सटीक आरोपों का भी उल्लेख नहीं किया है। यह प्रेस की स्वतंत्रता पर एक जबरदस्त हमला है। एफआईआर के अनुसार, मजूमदार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2)/3(1)(आर) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने आरोपों की वैधता पर सवाल उठाए हैं। 25 मार्च को शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट किया गया कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी *सार्वजनिक रूप से* की जानी चाहिए। हालांकि, कथित तौर पर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इस बीच, जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, पत्रकारों ने मजूमदार की रिहाई और उन पर लगे आरोप हटाए जाने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है। गुवाहाटी प्रेस क्लब ने भी मीडिया संगठनों से देशव्यापी समर्थन का आह्वान किया है और कहा है कि एक पत्रकार पर हमला *पूरे प्रेस समुदाय पर हमला* है।

सरकार वन्यजीवों की...

असम की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और उन्नत बुनियादी ढांचे ने पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि असम एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। घरेलू पर्यटकों के अलावा, सीएम शर्मा ने कहा कि 2021 से 60,000 से अधिक विदेशी आगंतुकों ने असम की यात्रा की है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बढ़ती आमद पर्यटन क्षेत्र में राज्य की वैश्विक उपस्थिति को और अधिक रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री ने इस वृद्धि का श्रेय कनेक्टिविटी बढ़ाने, सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करने तथा इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई कई सरकारी पहलों को दिया। अपने हरे-भरे प्राकृतिक इश्यों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन्यजीव अभ्यारण्यों और जीवंत त्योहारों के साथ, असम भारत में शीर्ष स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में लगातार पहचान हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य (केएनपीटीआर) में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, खासकर पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दौरा करने के बाद। प्रधानमंत्री मोदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रात बिताने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। वे लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले मार्च 2024 में वहां गए थे।

मातृ वंदन योजना ...

महिलाओं को इस योजना के तहत केवल एक किश्त ही दी गई। इसके अगले ही साल इसमें भारी गिरावट आई और आंकड़ा 12 फीसदी पर आ गया। सोनिया गांधी ने कहा कि एनएफएसए के तहत पूर्ण प्रसव के दौरान दिए जाने वाले इस लाभ के लिए 12000 करोड़ रुपए वार्षिक बजट की जरूरत है। यह आश्चर्यजनक है कि बजट में एनएफएसए के तहत मातृ वंदन योजना के लिए आवंटन का आंकड़ा ही नहीं दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने मिड डे मील में उपयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा को 10 प्रतिशत तक कम करने का मुद्दा उठाया। डोला सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों में मोटापे को देखते हुए स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में तेल की खपत में 10 प्रतिशत कम करने की नीति तैयार की जा रही है। बिना किसी अध्ययन के इस तरह की नीति सही नहीं है। स्कूलों में दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। उस पर उनके खाने में 10 प्रतिशत तक वसा को कम करने की नीति पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में वसा (फैट) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना किसी रिसर्च और अध्ययन के इस तरह स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन में फैट की मात्रा को 10 प्रतिशत तक की कमी करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश से भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने गाजीपुर में सेना की कैंटीन शुरू करने की मांग उठाई।

ईसी ने पहली बार ...

तमिलनाडु के 24 ईआरओ और 13 डीईओ सहित बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ इस 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण की यह योजना बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने और निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त करके अपडेट करने के लिए संगत फॉर्मों को भरने की अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराने के लिए बनाई गई है। उन्हें उन आईटी अनुप्रयोगों से भी परिचित कराया जाएगा जो उनके कार्य में सहायता देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बीएलओ राज्य सरकार के पदधारी होते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के अनुमोदन के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त तरीके से अपडेट करने में ईआरओ और बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों को एसडीएम स्तर या उनके समकक्ष अधिकारियों को ईआरओ के रूप में नामित करना चाहिए, जो बीएलओ की वरिष्ठता पर सम्यक विचार करते हुए उन अधिकारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्ति करने पर विचार करें जो उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान केंद्र के सामान्य निवासी हों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार भारत के ऐसे नागरिक ही निर्वाचक बन सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन-दक्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने स्तरों पर सर्वदलीय बैठकें आयोजित करने और निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने सहित अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को सुलझाने के संबंध में अपने दिए गए निदेशों को दोहराया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने इस बात के लिए भी सचेत किया कि ईआरओ या बीएलओ के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बीएलओ को निर्वाचक नामावली को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करने के दौरान निर्वाचकों के साथ बातचीत में विनम्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग हमेशा से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। इस आशय की जानकारी संयुक्त निदेशक पी पवन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

दुष्कर्म पर इलाहाबाद एचसी ...

बीते दिन मंगलवार को एससी ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुद से नोटिस लिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। कोर्ट ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है। एससी की सुनवाई में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि उन पर रोक लगाना जरूरी हो जाता है। इस फैसले के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में जिस तरह की बातें लिखी हैं, उनसे लोगों में बहुत गलत मैसेज गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यह देखना चाहिए कि इस जज को संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने न दिया जाए। जजों ने कहा कि यह फैसला तुरंत नहीं लिया गया, बल्कि सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। यानी पूरे विचार के बाद फैसला दिया गया है। फैसले में कहीं गई कई बातें कानून की दृष्टि से गलत और अमानवीय लगती हैं। ऐसे में हम इस फैसले पर रोक लगा रहे हैं और सभी पक्षों को नोटिस जारी कर रहे हैं। 17 मार्च को आए इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता को खींच कर पुलिया के नीचे ले जाना, उसके ब्रेस्ट को पकड़ना और पायजामे के डोरी को तोड़ना रेप की कोशिश नहीं कहलाएगा। 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का निष्कर्ष था कि यह महिला की गरिमा पर आघात का मामला है। इसे रेप या रेप की कोशिश नहीं कह सकते।

दिल्ली के बाद अब...

करती है। अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक की खासियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्वरोजगार और लघु उद्यमिता का विकास होगा। साथ ही सामाजिक समावेश बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नामकरण इस आधार पर किया गया है क्योंकि यह सहकारिता के एक ऐसे मॉडल पर आधारित है, जिसने पूरी दुनिया को चकित किया। उनका कहना था कि यह नाम एक ऐसे व्यक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और ईमानदारी से सहकारिता के सिद्धांतों को जीवन में उतारा। गौरतलब है कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 एक प्रस्ताविक विधेयक है, जिसे तीन फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। साथ ही इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारिता के सिद्धांतो पर आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। पारित विधेयक के अनुसार यह विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास, कृषि, स्वरोजगार, लघु उद्यमिता और समाजिक समावेश के क्षेत्र में शिखा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

उत्तरी गाजा में हमास...

होने के बाद से सबसे बड़ा है। ये विरोध बेत लाहिया में इजरायली सेना द्वारा लगभग दो महीने के युद्धविराम के बाद तीव्र बमबारी फिर से शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुआ। हमास बाहर जाओ और हमास आतंकवादी के नारे सड़कों पर गूंजने लगे। प्रदर्शनकारियों, जिनमें से ज्यादातर पुरुष थे, उन्होंने युद्ध बंद करो, हम शांति से रहना चाहते हैं और हम खाना चाहते हैं लिखे बैनर लहराए। अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन गाजा के नागरिकों के बीच गहरी निराशा को उजागर करता है जो एक अथक युद्ध की गोलीबारी में फंस गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्क टेलीग्राम के माध्यम से लामबंद किया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, हमास के सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य सिविल ड्रेस में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल एक अन्य व्यक्ति माजदी ने कहा कि लोग अब थक चुके हैं। अगर हमास के सत्ता छोड़ने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, तो उसे ऐसा कर देना चाहिए। वहीं हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले जारी रहे तो वह बंधकों की हत्या कर देगा। इजराइल का बलपूर्वक बंधकों को छुड़ाने का सपना पूरा नहीं होगा। *अरब न्यूज* के अनुसार, समूह ने आज दोहा में जारी बयान में कहा कि वह बंधकों को मारना नहीं चाहता। वह उन्हें जीवित रखने के हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इजराइल के गाजा में बरसते बम उनके जीवन को पल-पल खतरे में डाल रहे हैं। हमास ने कहा कि इजराइल ने कई बार बंधकों को बलपूर्वक वापस लेने का प्रयास किया है। हर बार उसे अपने लोगों को ताबूतों में ले जाना पड़ा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। गाजा पट्टी में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइल के पिछले सप्ताह शुरू हुए हमले में अब तक कम से कम 830 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के ताजा हमलों के बाद संघर्ष विराम टूट चुका है। अल जजीरा न्यूज चैनल के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गाजा पर इजराइली हमलों में कम से कम 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और मलबे से एक शव बरामद किया गया है। इजराइल के सुरक्षा बल (आईडीएफ) सीरिया पर भी बम बरसा रहे हैं। इस बमबारी में डेरा में कम से कम छह लोग मारे गए हैं। कतर और सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। उधर, अमेरिका की सेना यमन पर बम बरसा रही है।

अब जिनपिंग ने ...

तीन निजी कंपनियों डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप और हुआक्सिन झोंगशान सिक्योरिटी सर्विस को जिम्मेदारी सौंपी है। पहले चरण में सिंध प्रांत में दो सीपीईसी बिजली परियोजनाओं पर 60 चीनी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये जवान सुरक्षा में लगी पाकिस्तानी सेना की निगरानी करेंगे। सीपीईसी के तहत सिंध प्रांत के थार कोल ब्लॉक में दो बिजली परियोजनाओं पर करीब 6,500 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, चीनी नागरिकों के पहले घेरे में चीनी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चीनी नागरिकों का बाहरी लोगों से कम से कम संपर्क हो। सुरक्षाकर्मी श्रमिकों की योजनाबद्ध आवाजाही सुनिश्चित करेंगे। इस योजना को दूसरे सुरक्षा घेरे में तैनात पाकिस्तानी सेना के साथ साझा किया जाएगा।

बिहार विस में उठी ...

सदन में प्रस्ताव लाए कि लालू यादव को भारत रत्न देने हेतु बिहार सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे। उनकी इस सिफारिश पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि प्रति वर्ष पद्म पुरस्कारों के साथ भारत रत्न देने की अनुशंसा की जाती है। लालू यादव को भारत रत्न देने का कोई विचार नहीं है। विजय चौधरी ने मुकेश रौशन से अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध भी किया, जिसे खारिज कर दिया। सदन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि लालू यादव को भारत रत्न देने की सिफारिश से जुड़ा कोई प्रस्ताव नीतीश सरकार के पास नहीं है। उनके इस जवाब से सदन में मौजूद राजद के सदस्यों को बड़ा झटका लगा। हालांकि जब मुकेश रौशन ने प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने इस मुद्दे पर वोटिंग कराने की घोषणा की। इसके बाद संकल्प को ध्वनि मत से सदन में खारिज कर दिया गया।

द. कोरिया में भीषण ...

लगे हैं। आग से जुड़ी घटनाओं में 200 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। एंडोंग और अन्य शहरों के अधिकारियों ने मंगलवार को स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 9,000 अग्निशमन कर्मी, 130 से अधिक हेलीकॉप्टर और सैकड़ों वाहन काम कर रहे हैं, लेकिन शुष्क मौसम और तेज हवाओं के चलते आग बुझाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस आग ने 43,000 एकड़ से अधिक भूमि को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही 1,300 साल पुराने बौद्ध मठ समेत सैंकड़ों संरचनाएं तबाह हो गईं। उइसियोंग में आग से सातवीं सदी का बौद्ध मठ गोउंसा पूरी तरह जलकर राख हो गया। दक्षिण कोरिया के गृह और सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, एंडोंग, उइसियोंग, सानशियोंग और उल्सान में 5,500 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। यह इलाका आग से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया था, लेकिन बाद में तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण आग फिर से फैल गई। आग से होने वाली तबाही के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी है।

लोस अध्यक्ष ने राहुल...

और पति-पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संबंध में वे नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि वह लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संख्या नियम 349 में वर्णित नियमों के तहत आचरण करें जो सदन की उच्च मर्यादा के अनुरूप रहना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में नेता विपक्ष पर की टिप्पणी का कोई कारण नहीं बताया। साथ ही राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सदस्य इस पर कुछ बोल पाते इससे पहले अध्यक्ष बिरला अपनी टिप्पणियों के बाद कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर उठकर चले गए। लोकसभा से बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं पता लोकसभा अध्यक्ष किस विषय पर बात कर रहे थे। अध्यक्ष ने जब टिप्पणी की और उन्होंने बोलना चाहा तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और वे उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं बोलने के लिए उठता हूं, तो वे मुझे नहीं बोलने देते। पिछले 8-10 दिनों में, उन्होंने मुझे कभी बोलने की अनुमति नहीं दी।

आरएसएस ने की बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता की अपील

गुवाहाटी (हिंस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हो रहे हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संघ ने इसे मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। यह मुद्दा बेंगलुरु के जनसेवा विद्या केंद्र में 21 से 23 मार्च तक आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उठाया गया, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावों के संबंध में आज गुवाहाटी के पलटन बाजार स्थित केशवधाम में आरएसएस उत्तर असम प्रांत द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तर असम प्रांत के कार्यवाह खगेन सैकिया, उत्तर असम प्रांत के प्रचार प्रमुख किशोर शिवम, उत्तर असम प्रांत के कार्यवाह डॉ. भूपेश शर्मा ने प्रकाश डाला। सैकिया ने बताया कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के समय विशेष रूप से हिंदू मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर हमले होते हैं। इसके अलावा, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं की जाती हैं, संपत्ति लूटी जाती है, महिलाओं का अपहरण कर उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है और जबरन धर्मांतरण

की घटनाएं भी सामने आती हैं। संघ ने स्पष्ट किया कि इन घटनाओं को केवल राजनीतिक हिंसा कहकर उनके धार्मिक पहलुओं को नजरअंदाज करना सच्चाई को छिपाने के समान होगा, क्योंकि पीड़ितों में बहुसंख्यक हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। बांग्लादेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। 1951 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 22 प्रतिशत थी, जो अब घटकर मात्र 7.95 प्रतिशत रह गई है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वहां हिंदुओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। पिछले वर्ष हुई हिंसा और नफरत की घटनाओं को सरकार द्वारा मिली कथित मौन सहमति भी चिंताजनक है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश की ओर से लगातार भारत विरोधी बयानबाजी दोनों देशों के संबंधों को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। संघ का मानना है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी देशों में अविश्वास और संघर्ष का माहौल बनाकर दोनों देशों के बीच अशांति फैलाना चाहती हैं। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों से अपील की है कि वे इस भारत विरोधी माहौल और पाकिस्तान जैसे देशों की *डीप स्टेट* की सक्रियता पर नजर रखें और इसे उजागर करें। सभा ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं, इसलिए एक स्थान पर हुई अशांति पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। संघ ने यह भी स्वीकार किया कि बांग्लादेश के हिंदू समाज ने इन अत्याचारों के विरुद्ध शांतिपूर्ण, संगठित और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट किया है। भारत और विश्वभर के हिंदू संगठनों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए हैं। संघ ने भारत सरकार की भी सराहना की, जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता को बार-बार दोहराया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह बांग्लादेश सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखे और वहां के हिंदू समुदाय की सुरक्षा, सम्मान और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करे। इसके अलावा, सभा ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की है कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अमानवीय कृत्यों को गंभीरता से ले और इन हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएं। सभा ने हिंदू समुदाय के नेताओं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अनुरोध किया कि वे बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के समर्थन में आवाज उठाएं। संघ ने कहा कि आरएसएस का संकल्प है कि सभी प्रकार के भेदभाव को नकारते हुए समरसता युक्त आचरण और प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली को अपनाकर एक मूल्य-आधारित समाज का निर्माण किया जाए। आरएसएस का मानना है कि यदि समाज में सभी नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे और एकता व समरसता के सिद्धांतों को अपनाएंगे, तो भारत न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। सभा ने सभी स्वयंसेवकों और समाज के प्रबुद्ध जनों से आह्वान किया कि वे सज्जन शक्तियों के नेतृत्व में पूरे समाज को साथ लेकर चलें और विश्व के समक्ष एक संगठित, समरस और सशक्त भारत का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

बीटीसी में फिर सत्ता में आएगा यूपीपीएल-भाजपा गठबंधन : यूजी ब्रह्म

बाक्सा (हिंस)। बाक्सा के बामबाड़ी में आज आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर में असम सरकार के मंत्री यूजी ब्रह्म ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बोड़ोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीटीसी में फिर से सत्ता में यूपीपीएल-भाजपा गठबंधन आएगा। उन्होंने कहा कि बीटीसी चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन हो या न हो, हमारी पार्टी यूपीपीएल चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही कहा कि बीटीसी में अकेले चुनाव लड़ना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ब्रह्म ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़े या न लड़े, बीटीसी में फिर से भाजपा-यूपीपीएल की ही परिषद सरकार बनेगी। इस दौरान बीपीएफ प्रमुख हग्रामा महिलारी की मंत्री ब्रह्म न तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हग्रामा महिलारी खुद ही अकेले पड़ गए हैं, वे अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे तो किसके साथ लड़ेंगे? यूपीपीएल नेता ब्रह्म ने कहा कि हग्रामा के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नव शरणिया का हग्रामा महिलारी साथ ले रहे हैं। वर्तमान में हग्रामा महिलारी के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें अकेले ही चुनाव लड़ना होगा। मंत्री यूजी ब्रह्म ने कहा कि बीटीसी में फिर से यूपीपीएल-भाजपा के नेतृत्व में संयुक्त सरकार बनना तय है। आज मंत्री ब्रह्म के साथ बीटीसी के पार्षद जय मुसाहारी, मोंटू बोडो, सालबाड़ी टीसीएलसीसी के अध्यक्ष बिनोद मुसाहारी सहित कई पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

पुलिस ने ड्रग्स तस्कर पर चलाई गोली, गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी की नूनमाटी पुलिस की एक टीम ने ड्रग्स तस्कर को पकड़ने के लिए उस समय गोली चलाई जब वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर ने आज बताया है कि इस मामले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि नूनमाटी थाना क्षेत्र के नारंगी तीनाली में बोलेरो (एएस-12एई-2086) को रोकने के लिए पुलिस ने बीती रात इशारा दिया, इस दौरान बोलेरो वाहन का चालक मौके से फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने वाहन को रोकने के लिए गोली चलायी। पुलिस का इशारा न मानकर वाहन लेकर भाग रहे व्यक्ति पीछा कर नूनमाटी पुलिस ने एक ड्रग्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा और ड्रग्स जब्त किया गया। हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सबिन बासुमतारी के रूप में की गई है। पुलिस इस संबंध में एनडीपीएस की धारा के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

बरपेटा के भेल्ला पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी

बरपेटा (हिंस)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बरपेटा के भेल्ला निवासी नासिरुद्दीन सरकार के घर पर आज सीआरपीएफ के निचले असम के डीआईजी सुनंद कुमार और 10वीं बटालियन के एसी दीपक कुमार सिंह सहित सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची। डीआईजी ने नासिरुद्दीन की पत्नी, पुत्र और पुत्री को ईद की शुभकामनाएं दीं और रमजान के अवसर पर एक छोटा सा उपहार भेंट किया। सीआरपीएफ टीम ने परिवार के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गौरतलब है कि 27 अप्रैल, 2024 को मणिपुर में कुकी उग्रवादियों के हमले में भेल्ला के बनबड़िया गांव निवासी नासिरुद्दीन बलिदान हो गए थे। सीआरपीएफ के जवान नासिरुद्दीन चुनावी ड्यूटी पूरी करने के बाद लौट रहे थे, तभी उग्रवादियों की गोलीबारी में बलिदान हो गए।

असम विधानसभा में राज्य स्तरीय *विकसित भारत युवा संसद* आयोजित

140 युवा प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी होंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा के नए भवन के सेंट्रल हॉल में आज राज्य स्तरीय *विकसित भारत युवा संसद* का भव्य आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में असम के सभी जिलों से चयनित 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 140 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन असम विधानसभा के अध्यक्ष बिश्वजीत दैमारी ने किया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति को गलत नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे गलत लोग बदनाम करते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आकर इसे बेहतर बनाना चाहिए। इस अवसर पर असम की खेल और युवा कल्याण मंत्री नंदिता गार्लोसा, खेल और युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव केजे हिलाली और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जिला स्तर की युवा संसद में चयनित प्रतिभागियों ने राज्य स्तरीय संसद में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर तीन सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिनिधियों का चयन किया गया, जो अब नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की *विकसित भारत युवा संसद* में भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करना, उनमें नेतृत्व कौशल का विकास करना और उन्हें नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की *विकसित भारत* की परिकल्पना को साकार करने में इस प्रकार के आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य स्तरीय *विकसित भारत युवा संसद* में युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि वे देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर असम के प्रतिनिधि अपनी क्षमता और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे, जिससे न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि वे भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभर सकते हैं।

मालीगांव में तेंदुए के हमले में किशोर घायल

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी के मालीगांव गौशाला इलाके के पूर्व माधवदेव नगर में एक तेंदुए के हमले में 12 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय निवासियों ने आज बताया है कि फारूक आली नामक किशोर पीने का पानी लेने के लिए बीती रात को एक झरने के पास गया था, इसी बीच अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसके सिर और गले पर गंभीर चोटें आईं हैं। किशोर की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत लाठी-डंडा लेकर बाहर निकले और उसे बचाने के लिए आगे आए। घटनास्थल पर तेंदुआ के पैरों के निशान स्पष्ट रूप से देखे गए, जिससे यह साबित होता है कि इलाके में तेंदुआ मौजूद है। स्थानीय निवासियों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बीती रात को तेंदुआ को इलाके में कई बार देखा गया था, लेकिन न तो वन विभाग ने और न ही पुलिस ने कोई सक्रियता दिखाई। जिसके चलते एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।

राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने की भाजपा सरकार की आलोचना

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के असम प्रभारी मनोज चौहान ने गुवाहाटी स्थित राजीव भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असम में इस समय अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संवैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और आम जनता पर पुलिस के जरिए अत्याचार किया है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस इस रवैए का विरोध करने के लिए जनता के बीच संघर्ष तेज करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सत्ता के अहंकार में लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री जितना दमन करेंगे, जनता में उतना ही आक्रोश बढ़ेगा, जिसका परिणाम 2026 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से डरते हैं। उन्होंने असम विधानसभा में हाल ही में हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा के एक विधायक ने विपक्षी विधायक पर हमला की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मनोज चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के उप-नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के खिलाफ झूठा प्रचार किया गया। इसके अलावा, नगांव में सांसद रकीबुल हुसैन पर दिनदहाड़े हमला किया गया और गोगामुख में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया। चौहान ने क्रॉस करंट के पत्रकार दिलावर हुसैन की गिरफ्तारी को भी षड्यंत्र करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने असम में कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले ही मुख्यमंत्री शर्मा को भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था और आज यह बात सच साबित हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के मामले देश में शीर्ष पर हैं। उन्होंने दावा किया कि कई पुलिस थाने शिकायतें दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं, जिससे अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। चौहान ने कहा कि असम में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के कारण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित छह विदेशी देशों ने असम को असुरक्षित घोषित किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इन तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सभी भ्रष्टाचार और अत्याचार के मामलों को जनता के सामने लाएगी।

जर्मन राजदूत ने असम के राज्यपाल से मुलाकात की

श्री आचार्य ने राजदूत के समक्ष असम की संभावनाओं को प्रस्तुत किया

गुवाहाटी। भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन ने आज राजभवन में असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और असम में हेरिटेज पर्यटन से लेकर राज्य में मौजूद निवेश संभावनाओं तक के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल श्री आचार्य ने भारत और जर्मनी के बीच दशकों पुराने द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि असम के भू-राजनीतिक महत्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से इसकी निकटता को देखते हुए, राज्य भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को और अधिक गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जर्मन इंडिया एकेडमिक नेटवर्क फॉर टुमॉरो के माध्यम से आईआईटी खड़गपुर और जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस के बीच मौजूदा सहयोग को देखते हुए, राज्यपाल ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ भी इसी तरह के सहयोग की वकालत की। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि इससे असम और जर्मनी के बीच शैक्षणिक संबंध मजबूत होंगे और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न एडवांटेज असम 2.0 के बारे में बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में विदेशी गणमान्य व्यक्तियों सहित 45, 000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया तथा 5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यपाल ने इस विकास का श्रेय पूर्वोत्तर के आर्थिक केंद्र तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में असम की क्षमता में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिया। राज्यपाल ने राज्य में तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों तथा विशाल चाय पर्यटन का उल्लेख करते हुए आध्यात्मिक तथा वन्य-जीव पर्यटन के लिए असम की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने असम तथा जर्मनी दोनों के लिए अर्थ जोड़ने तथा पारस्परिक लाभ बढ़ाने के लिए इन स्थानों की खोज करने के लिए जर्मन दूत का ध्यान आकर्षित किया। राजदूत के साथ महावाणिज्य दूत बारबरा वॉस भी थीं।

जीबी कॉलेज, मोरीगांव के साथ वैज्ञानिक बकरी पालन पर सीआईटीए प्रायोजित परियोजना का उद्घाटन किया गया

गुवाहाटी। राज्य नवाचार एवं परिवर्तन आयोग (सीआईटीए) के उपाध्यक्ष नारायण चंद्र बोरकाटकी ने 26 मार्च, 2025 को घनकांता बरुआ कॉलेज, मोरीगांव में जराबारी एग्रो प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में सीआईटीए प्रायोजित परियोजना *वैज्ञानिक बकरी पालन* का उद्घाटन किया। बैठक में उपाध्यक्ष नारायण चंद्र बोरकाटकी ने जीबी कॉलेज, मोरीगांव के प्राचार्य डॉ. बिष्णु प्रसाद उपाध्याय को परियोजना के लिए नौ लाख साठ हजार रुपए की पहली किस्त भी सौंपी। यह कार्यक्रम टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से समर्थित कृषि पद्धतियों के साथ कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम था। समारोह की शुरुआत वैज्ञानिक बकरी पालन पहल के औपचारिक परिचय के साथ हुई। जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने, पशुधन की गुणवत्ता बढ़ाने और महिला लाभार्थियों के लिए बेहतर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करके बकरी पालन में क्रांति लाना है। परियोजना का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यावहारिक कौशल से सशक्त बनाना और बकरी पालन में कौशल को सशक्त बनाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य बकरी पालन को लाभदायक व्यवसाय उद्यम के रूप में अपनाने के लिए महिला किसानों की तकनीक और क्षमता निर्माण के प्रसार के लिए एक ग्राम स्तरीय ज्ञान साझाकरण केंद्र स्थापित करना भी है। यह योजना चार क्लस्टरों में तैयार की गई है, जिनमें से प्रत्येक में 20 महिला लाभार्थी हैं।

प्रत्येक क्लस्टर को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके बाद फार्म शुरू करने से पहले लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। इस अवसर पर बोलते हुए, माननीय उपाध्यक्ष नारायण चंद्र बोरकाटकी ने स्थानीय समुदायों के उत्थान और देश के कृषि विकास में योगदान देने में वैज्ञानिक खेती प्रथाओं के महत्व पर बल देते हुए सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कदम है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। परियोजना के प्रारंभ होने और पहली किस्त जारी होने के साथ ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वैज्ञानिक बकरी पालन पहल क्षेत्र में बकरी पालन प्रथाओं के लिए एक नया मानदंड स्थापित करेगी, जिससे महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने में सहायता मिलेगी और साथ ही एक अधिक टिकाऊ कृषि भविष्य में योगदान मिलेगा। बैठक में सह-उपाध्यक्ष ध्रुबा प्रसाद बैश्य ने आगे बताया कि यह पहल बकरी पालन की गुणवत्ता में सुधार, बकरी किसानों के लिए उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने और ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी और उम्मीद है कि एसआईटीए द्वारा प्रायोजित यह परियोजना पशुधन और मुर्गीपालन की उत्पादकता बढ़ाने में सफल होगी और साथ ही महिला कृषक समुदाय के कौशल को उन्नत करेगी।

मराण टी ईस्टेट ने जीता सेलिब्रेशन कप 2025 का फाइनल

मोरान। मैकडोवेल्स सेलिब्रेशन कप 2025 के दूसरे सीजन का समापन मराण टी ईस्टेट की शानदार जीत के साथ हुआ, जिन्होंने फाइनल में खोवांग टी ईस्टेट को 2-0 से हराया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में विभिन्न टी ईस्टेट क्षेत्रों से 16 टीमों ने भाग लिया, जो बेहद सफल रहा। इस आयोजन ने न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को दुनिया के समक्ष रखा बल्कि सामुदायिक जज्बे को भी बढ़ावा दिया। मैकडोवेल्स नंबर 1 सोडा सेलिब्रेशन कप एक वार्षिक खेल टूर्नामेंट है, जिसे स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ियों का समर्थन करने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह आयोजन खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और खेलों के माध्यम से समुदायों को एकजुट करने का लक्ष्य रखता है। मराण टी एस्टेट के आमगुरी मैदान में आयोजित फाइनल मुकाबला मराण टी ईस्टेट और खोवांग टी ईस्टेट के बीच था जो कि एक रोमांचक मुकाबला रहा।

मराण टी ईस्टेट ने 20 की शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की। इस आयोजन के दौरान हाफटाइम ब्रेक में लोकप्रिय कलाकार राकेश रियान की लाइव परफॉर्मेंस भी हुई, जिसने दर्शकों में और भी ज्यादा जोश भर दिया।

संपादकीय

संविधान, आरक्षण पर सियासत

संविधान में संशोधन संसद में ही किया जा सकता है। यह संसद का विशेषाधिकार है। संविधान में संशोधन विधानसभा के स्तर पर नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रस्तावित बिल को विधानसभा पारित करना चाहती है, तो उसे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। यह उनका विशेषाधिकार है कि बिल पारित करें या उसे लौटा दें। संसद में अभी तक 106 संविधान संशोधन पारित किए जा चुके हैं। संविधान पर फिजूल ही सियासत की जा रही है। चूंकि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कराया है, लिहाजा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 'संविधान बदलने' का जो बयान दिया है, वह बेमानी, असंवैधानिक है। भाजपा ने इसे लपक लिया है। उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने तक की मांग की गई है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान में बाबा अंबेडकर ने साफ किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस उसे बदलने की कोशिश कर रही है। संविधान बचाने की सियासत अब भाजपा के हाथों में है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक फर्जी नेरेटिव फैलाया गया था कि भाजपा सरकार में आई, तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। इस नेरेटिव का विपक्षी दलों को अच्छा फायदा मिला और उनकी संसदीय सीटें बढ़ गईं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहली बार सामान्य बहुमत हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही ठहर गई। संविधान और आरक्षण पर सियासत क्यों और कैसे की जा सकती है, जबकि ये हमारे लोकतंत्र के स्थापित सत्य हैं। संविधान सभा के जरिए भारत का संविधान तय किया गया और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए ही था, लेकिन संविधान लागू हुए 75 लंबे साल गुजर चुके हैं, लेकिन आरक्षण आज भी जारी है। अब तो आरक्षण एक राजनीतिक हथियार और वोट बैंक का आधार बन चुका है। हमारे पुरखों ने जो संविधान तैयार किया था, उसके अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, रंग, नस्ल और मूल वंश के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16 में पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर रखी है, लेकिन राज्य सरकारें 'संवैधानिक चालाकी' खेल कर, पिछड़ों के कोटे में ही, अन्य वर्गों को आरक्षण का प्रस्ताव पारित कराती रही हैं। कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण ऐसा ही है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा बढ़ा कर 42 फीसदी कर दिया है। यकीनन ये संविधान का उल्लंघन हैं और सर्वोच्च अदालत इन आरक्षणों को निरस्त कर सकती है। दरअसल यह अपना वोट बैंक पुख्ता करने और बढ़ाने की सियासत भर है। दरअसल अब 2025 में आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। जिनके लिए करोड़ों रुपए के ठेके में आरक्षण तय किया गया है, जाहिर है कि वे इतने सम्पन्न, समृद्ध तो होंगे कि ठेके ले सकें और फिर काम कर सकें। बहरहाल, आरक्षण की समीक्षा ही समाधान है।

संविधान में संशोधन विधानसभा के स्तर पर नहीं किया जा सकता। यदि किसी प्रस्तावित बिल को विधानसभा पारित करना चाहती है, तो उसे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। यह उनका विशेषाधिकार है कि बिल पारित करें या उसे लौटा दें। संसद में अभी तक 106 संविधान संशोधन पारित किए जा चुके हैं। संविधान पर फिजूल ही सियासत की जा रही है। चूंकि कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कराया है, लिहाजा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 'संविधान बदलने' का जो बयान दिया है, वह बेमानी, असंवैधानिक है। भाजपा ने इसे लपक लिया है। उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने तक की मांग की गई है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान में बाबा अंबेडकर ने साफ किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस उसे बदलने की कोशिश कर रही है। संविधान बचाने की सियासत अब भाजपा के हाथों में है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक फर्जी नेरेटिव फैलाया गया था कि भाजपा सरकार में आई, तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी।

शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फिर संविधान बचाने का सियासी अभियान हावी हो गया है

संविधान के नाम पर कांग्रेस का दोहरा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण

ललित गर्ग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर हाथ में संविधान की प्रति लेकर भाजपा पर इसे बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अपनी हर सभा में इस आरोप को दोहराते रहे कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, इसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद संविधान बदलने की बात कर रही हैं। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ओबीसी कोटा के तहत पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है

कांग्रेस एक बार फिर संविधान को लेकर विवादों से घिर गयी है। संविधान के संबंध में कांग्रेस का दोहरा रवैया एवं चरित्र एक बार फिर देश के सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर हाथ में संविधान की प्रति लेकर भाजपा पर इसे बदलने का आरोप लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय अपनी हर सभा में इस आरोप को दोहराते रहे कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल कर आरक्षण खत्म कर देगी, इसका भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस आज खुद संविधान बदलने की बात कर रही हैं। दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ओबीसी कोटा के तहत पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण देने जा रही है, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में जब उप- मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को यह याद दिलाया गया कि संविधान के तहत मजहब के आधार पर आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने इशारा किया कि आरक्षण देने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे। शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक फिर संविधान बचाने का सियासी अभियान हावी हो गया है। इस बार भाजपा आक्रामक है और उसने फिलहाल इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। इस वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह अहम मुद्दा बन जाये तो कोई आश्चर्य नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये कांग्रेस सरकारें अपने-अपने राज्यों में अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं योजनाएं लागू करती रही हैं, कर्नाटक में भी वहां के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने सरकार का बजट पेश करते हुए मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4 प्रतिशत अब श्रेणी-प्प बी के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इसका निर्माण वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पर पैसा खर्च करेगी। मौलवियों को 6000 मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समुचित बजट आवंटित नहीं हुआ लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के

चलते मुस्लिमों के लिये लुभावना बजट आवंटित किया गया है। जबकि सरकारों का काम किसी धर्म एवं समुदाय विशेष का तुष्टिकरण न होकर सभी समुदायों का पुष्टीकरण होना चाहिए। जब संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का निषेध किया गया है तो फिर जानबूझकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे सूचीबद्ध करके विधि सम्मत क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल, भाजपा और कांग्रेस, दोनों देश की प्रमुख पार्टियों को यह एहसास हो चला है कि संविधान इस देश में बहुत संवेदनशील विषय है और इस पर लोग कतई समझौता नहीं करेंगे। संविधान केवल न्यायिक या वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह भारत की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस अर्थ में यह देश के जन-जन के मन का दस्तावेज है। संविधान भारत में सभी नागरिकों के लिए दिग्दर्शक तत्व है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान इतना स्पष्ट है तो क्या संविधान की मूल भावना पर केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए आघात करना स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पवित्र ग्रंथ पर भी विपक्षी दल एवं कांग्रेस अत्यंत निकृष्ट राजनीति करती जा रही है। जो कांग्रेस शासन में रहते हुए कभी संविधान का सम्मान नहीं कर सकी, वह आज विपक्ष में बैठकर यह भ्रम फैलाने में लगी है कि मोदी सरकार संविधान को खत्म कर देगी। सच तो यह है कि कांग्रेस जैसे दल आज अपने मूल राजनीतिक विचार को खो बैठे हैं। कांग्रेस अपने गांधीवादी विचार और समाजवादी पार्टी जैसे दल समाजवाद और राम मनोहर लोहिया के मूलभूत विचारों को भूल चुके हैं। संविधान को आधार बनाकर विपक्षी दल जनता को विभाजित करने, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेंकने बाज नहीं आ रहे हैं। आश्चर्य नहीं, कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो हथियार चलाया था, वही हथियार कर्नाटक में स्वयं कांग्रेस के विरुद्ध चला गया है। अब इससे होने वाले नुकसान का भान होते ही कांग्रेस तत्काल बचाव में लग गई। वैसे, शिवकुमार के स्पष्टीकरण के बावजूद भाजपा इस मुद्दे पर निशाना साध रही है, तो संकेत साफ है, वह सियासत का मौका जाने नहीं देना चाहेगी। वह संविधान बदलने और न बदलने पर फिर से गर्म हुई राजनीति को ठंडा नहीं होने देगी। बीते लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा निशाने पर थी, वहीं इस बार कांग्रेस निशाने पर आ गई है। लोकसभा-राज्यसभा में एवं इस वर्ष बिहार में होने वाले चुनावों में भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक रहेगी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, भले ही अब कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार सफाई देने में लगे हैं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और वह संविधान में बदलाव का प्रस्ताव कभी नहीं रखेंगे। स्पष्ट है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का पक्षधर नहीं है। डॉ. भीमराव आंबेडकर भी ऐसे आरक्षण के हिमायती नहीं थे। संविधान सभा में एकमत के साथ यह तय हुआ था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब अगर ऐसे आरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है, या कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिये आरक्षण का हथियार चलाती है तो संविधान में संशोधन तो करना ही होगा। अपने आजाद देश में जरूरतमंदों को आरक्षण देने के लिए करीब 12 बार संविधान में संशोधन किए गए है और मुस्लिमों को महज मजहबी बुनियाद पर आरक्षण देने के लिए भी ऐसी जरूरत पड़ेगी। गांधी परिवार के अत्यंत करीबी कर्नाटक के डिप्टी सीएम के बयान को सुनकर लोग हैरत में हैं। लोग संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में संविधान की धज्जियां उड़ा दी है।' कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण के लिये देश को दांव पर लगाती रही है। एक बार फिर उसकी इस कोशिश से उसका असली चेहरा देश के सामने आया है।

दृष्टि कोण

कचरा-कचरा जिंदगी, समस्या और समाधान

सबसे ज्यादा समस्या प्लास्टिक कचरे से पैदा हो रही है। वैसे तो यह सार्वभौमिक समस्या बन गई है, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो यहां की पर्यटन पर आधारित आजीविका के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। इस समय दो करोड़ के लगभग पर्यटक वर्षभर में आते हैं। यानी यहां की जनसंख्या से तीन गुणा। सरकार इस संख्या को पांच करोड़ करना चाहती है। आर्थिक दृष्टि से यह आजीविका और सरकारी आय के लिए लाभप्रद ही सिद्ध होने वाला है। किंतु पर्यटन अपने साथ अनेक समस्याएं और प्रकृति पर दबाव भी लाता है। इनमें से कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी भी अवश्यंभावी समस्या है। वर्तमान कचरा प्रबंधन की स्थिति देख कर लगता है कि हम आने वाले दबाव को कैसे झेल पाएंगे, जबकि वर्तमान स्थिति को ही हम संभालने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। शहरों में भी कचरा जगह-जगह खुले में जलाने के दृश्य देखे जा सकते हैं। यहां तक कि कचरा निष्पादन स्थलों में भी कचरा जलाया जाता है। यह सीधा बीमारी को निमंत्रण है। गांव की तो हालत और भी खराब है। आजकल ज्यादातर दैनिक जरूरतों के सामान पैकिंग में ही आते हैं। कुरकुरे, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट, करियाने का सामान, दूध, दही, सब प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के बाबजूद यह सब पैकिंग का कचरा तो आ ही रहा है, इसके साथ सब्जियों का बाहरी राज्यों से जो आयात हो रहा है, वह ज्यादातर प्लास्टिक की पन्नियों में ही हो रहा है। इस तरह कचरे के अंबार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर चिकित्सा से जुड़ी सामग्री, बिजली के बल्ब, बैटरियां, इलेक्ट्रोनिक सामान शहरों से लेकर गांव तक चारों ओर फैलते जा रहे हैं। खेत-खलिहान, कूहलें, वन क्षेत्र कचरे की चपेट में हैं। जब तक कोई

निश्चित व्यवस्था खड़ी नहीं होती, तब तक लोगों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि विकल्प देकर ही सख्ती भी की जा सकती है। उसके बिना तो लोग भी मजबूरी में गैरजिम्मेदार हो जाते हैं। हिमाचल में प्रतिदिन 370 मीट्रिक टन सूखा कचरा पैदा होता है, जिसके लगातार बढ़ते जाने की संभावना है। शहरों में कम से कम कचरा एकत्र करने की व्यवस्थाएं तो हैं, आगे उसका निष्पादन कैसे हो, यही समस्या आंशिक रूप से है। गांव की तो हालत और भी बुरी है। वहां तो कचरा एकत्रित करने की बुनियादी व्यवस्थाएं ही नहीं हैं। प्लास्टिक तो सब जगह पहुंच गया है। गांव में पहले तो केवल जैविक कचरा ही होता था, जिसका खाद बना लो या जला कर भी उतनी हानिकारक गैसें नहीं निकलती थीं। अब गांववासी उसी पुरानी सोच के साथ चल कर कचरे की समस्या से पार नहीं पा सकते। अतः गांव में पंचायतों के माध्यम से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पालमपुर की आईमा पंचायत की बहुप्रचारित कचरा प्रबंधन व्यवस्था भी अब बंद पड़ गई है। उसका अध्ययन करके व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मोटे तौर पर हर घर से महीने में एक बार कम से कम कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके लिए पंचायत उपयुक्त राशि निर्धारित कर सकती है जो हर परिवार महीने के अंत में स्वयं कचरा इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ता को दे सकता है। पंचायतों में अधिकांश जगह कचरा एकत्रित करने के लिए स्टोर बना दिए गए हैं। अब उनके प्रयोग करने की ओर ध्यान देना होगा। गांव में जैविक कचरा उठाने की जरूरत नहीं है। उसका खाद बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक में भी मोटा प्लास्टिक कबाड़ी को बेचा जा सकता है। ठंडे की बोतलें भी बिक जाती हैं। उनके लिए केवल सख्ती से जागरूक करने की जरूरत है। अगली चुनौती एकत्रित किए गए कचरे के निष्पादन की है। इसके लिए तो सरकार को दीर्घकालीन योजना बना कर काम करना चाहिए और उसके क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। तकनीकी व्यवस्था अगली चुनौती है। नई-नई खोजें हो रही हैं। उनका उपयोग किया जाना चाहिए। एकमुखी समाधान से काम नहीं चलेगा। स्थानीय स्थितियों के अनुसार विविध प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए प्लास्टिक बनाने और प्लास्टिक में पैक सामान बेचने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

कुछ अलग

और दोस्त, कैसे हो...

पिछले हफ्ते अपना खास दोस्त चला गया। होटल में बैठ उसी की शोकसभा मना रहा था कि उसका फोन आ गया, 'क्या कर रहे हो?' 'तुम्हारी शोकसभा मना रहा हूं और क्या', मैंने उसकी शोकसभा मनाते चाय का घूंट लिया तो उसने पूछा, 'अकेले ही?'

'अब अकेले ही खुशी-गम सेलिब्रेट करने पड़ते हैं दोस्त!'

'वो मेरी कविता पर आह! आह! करने वाले सब कहां हैं?'

'वे सब अपनी अपनी शोकसभाओं, श्रद्धांजलियों में व्यस्त हैं, सो सोचा, मैं तो कम से कम समय पर तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारी विधिवत शोक सभा आयोजित कर तुम्हें श्रद्धांजलि दे दूं ताकि मेरी आत्मा की शांति मिले। तुम अभी भी यहीं हो क्या? गए नहीं?' 'जाऊंगा कैसे? उस प्रोग्राम का पारिश्रमिक तुम्हारे खाते में आ गया क्या? यार क्या बंदे हैं ये भी? हर बार पारिश्रमिक का फार्म भरवा उल्लू बना देते हैं, हमारी कविता पढने की विवशता का फायदा उठा', उसने जिंदा रहने वाली मरने के बाद भी आपत्ति दर्ज की, 'देखो दोस्त! जब तक वह तुम्हारे खाते में नहीं आएगा, मैं यहां से जाने वाला नहीं।' बेशर्म कहीं का! खुद तो मर गया, पर कंबख्त कविता का पारिश्रमिक अभी भी जिंदा है, 'और अपने क्रिया कर्म से फ्री हुए कि नहीं?'

'आज हो गया!' मत पूछो उसने कितने संतोष से कहा, 'कैसा रहा?'

'ठीक रहा! मस्त मस्त! अपने क्रिया कर्म से बहुत खुश हूं', सुनकर अच्छा लगा, 'अब कहां जाने का सकोप है?' मैंने यों ही पूछा तो वह चुप हो गया। मैंने पुनः पूछा, 'अब कहां जाने की उम्मीद लग रही है?'

'रहने दे! सच कहूंगा तो लाखों करोड़ों के धंधे बंद हो जाएंगे। पेट पर ताले लग जाएंगे।' हद है यार! सच कहने में अभी भी आपत्ति! ठीक है, 'तो मुझे फोन किसलिए किया था?'

'हां यार! एक बात करनी थी। देख, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा।'

'सो पता तो किसी को भी नहीं होता', मैं भाड़े का टट्टू दार्शनिक बना, 'बोल, अब क्या बचा है तेरा यहां?'

'कविताओं के पारिश्रमिक के अतिरिक्त मेरे घर में मेरी किताबें हैं यार! हो सके तो उन्हें वहां से ले जाना। मैंने अपनी ही तरह के मुझसे पहले गुजरे लेखक के मरने के बाद देखा था कि उसकी किताबें उसके कमरे से हटा वहां गेस्ट रूम बना दिया गया था।' किताबों के प्रति मरने के बाद भी उसकी श्रद्धा देख मन मोर हो बैठा, 'तो?' 'मेरी किताबें वहां से ले जाना। तेरा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। और हां! मेरी कुछ अप्रकाशित कविताएं भी हैं उनमें। भले ही उन्हें अपने नाम से छपवा लेना। मुझे बुरा नहीं लगेगा। यहां तो लोग लेखक के जिंदा रहते ही उसकी रचनाएं उसके मुंह के सामने ही अपनी बता पारिश्रमिक ले हवा होते रहे हैं। तेरे नाम से ही सही, इस बहाने कम से कम मेरे विचार कागजों से निकल हवा में तो तैर जाएंगे। उनमें कोई सांस ले या न! वैसे भी अब समाज को गंदी हवा में सांस लेना रास आने लगा है।' 'देखो दोस्त! माना तुम मेरे दोस्त हो। पर सच ये है कि किताबों की रद्दी को आजकल कबाड़ी भी नहीं लेते। पिछले हफ्ते मैंने भी अपनी किताबें निकालनी चाही थीं। पर उसने साफ-साफ कह दिया था कि और तो छोड़ो, इनसे तो आलू प्याज के लिफाफे तक नहीं बनते। कबाड़ी किताबों की रद्दी से सौ गुणा बेहतर अखबारी रद्दी को मानते हैं।' मैंने उसका फोन काटा और उसे श्रद्धांजलि देने में व्यस्त हो गया।

देश दुनीया से

स्कूल शिक्षा को उत्कृष्ट कैसे बनाएं?

दूसरे देशों की बेहतर शिक्षा प्रणाली से सीखने के लिए हमारे देश में लगातार कोशिश की जा रही है। कुछ राज्य अपने स्कूल अध्यापकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वहीं आजकल हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी स्कूल शिक्षा में बेहतर कारगुजारी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में आ रहा है। यहां तक कि अमरीका जैसा सुपर पावर देश भी स्कूल शिक्षा को लेकर श्रीलंका के प्रदर्शन को लेकर बौना साबित हो रहा है। स्कूली बच्चों की पढ़ाई के मामले में श्रीलंका ने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत के साथ सांस्कृतिक सांझ रखने वाले श्रीलंका ने दिखा दिया है कि सही मेहनत और सही सोच हो, तो छोटा देश भी बड़े देशों से आगे निकल सकता है। यह खुलासा हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें बताया गया है कि श्रीलंका को अमरीका से 0.7 नंबर ज्यादा मिले हैं, जो दिखाता है कि पढ़ाई के मामले में श्रीलंका ने छोटा-सा अंतर होने के बावजूद अमरीका जैसे महाबली को हरा दिया। श्रीलंका की पढ़ाई की व्यवस्था को इतना अच्छा बनाने के पीछे कई कारण हैं जो हमारे लिए भी सीखने का सबब हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां की सरकार ने हर बच्चे को पढ़ाने को सबसे जरूरी काम माना है। गांवों में भी स्कूल बनाए गए हैं और वहां पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। श्रीलंका में करीब 31 हजार स्कूल हैं, जो इतने छोटे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका में पढ़ाई तक पहुंच भी बहुत अच्छी है। वहां 98 प्रतिशत बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और 85 फीसदी से ज्यादा बच्चे हाई स्कूल तक पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां गरीब और अमीर सभी बच्चों को पढने का मौका मिलता है।

वहां की सरकार ने मुफ्त स्कूल और स्कॉलरशिप की सुविधा दी है, ताकि पैसों की कमी की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। श्रीलंका में पढ़ाई की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वहां टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे बच्चों को नए और आसान तरीकों से पढ़ा सकें। स्कूलों में बच्चों को किताबों के साथ-साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी और स्किल्स सिखाना। श्रीलंका में स्कूलों का सिलेबस भी समय के साथ अपडेट किया जाता है, ताकि बच्चे आज के समय की जरूरतों के हिसाब से पढ़ सकें। क्या हम यह सब अपडेट कर रहे हैं? श्रीलंका की पढ़ाई की एक खास बात यह है कि वहां बच्चों को सिर्फ किताबें रटने को नहीं कहा जाता। स्कूलों में खेल, कला और अच्छे संस्कार सिखाने पर भी ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी में भी बेहतर बनते हैं। कुछ देशों में पढ़ाई ज्यादा ग्लोबल होती है, लेकिन लोकल चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादातर पढ़ाई पर ही जोर रहता है, लेकिन श्रीलंका में बच्चों को अच्छा इनसान बनाना भी जरूरी समझा जाता है। श्रीलंका ने अपनी पढ़ाई में पर्यावरण और अपनी संस्कृति को भी शामिल किया है। बच्चों को अपने आसपास की प्रकृति और अपनी परंपराओं के बारे में सिखाया जाता है, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। श्रीलंका का यह तरीका बच्चों को जिम्मेदार और समझदार बनाता है। कुल मिलाकर श्रीलंका की स्कूल शिक्षा में कुछ ऐसे सारगर्भित गुण हैं जिनसे हम अपनी स्कूल शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसी के साथ हमें अपने देश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आयु के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, एनआईओएस, एसआईओएस के माध्यम से शिक्षा पूरी करने के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों (16 से 19 वर्ष) को सहायता, समग्र प्रगति कार्ड, द्विभाषी शिक्षण सामग्री और पुस्तकें मुहैया कराना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने, सुदृढ़ करने, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, एसटी आबादी के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छात्रावासों का निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने होंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और विकलांग छात्राओं को मासिक वृत्ति आदि प्रदान की जानी चाहिए। इसमें स्कूलों में बाधामुक्त पहुंच के लिए रैंप, हैंडरेल के साथ रैंप और विकलांगों के अनुकूल शौचालय जैसे दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। जिस देश और राज्य की स्कूल शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि की होती है, वह देश बहुत तेज गति से विकास करता है। अतः प्रत्येक देश के विकास में उस देश की शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान होता है। वर्तमान में हमारी स्कूल शिक्षा प्रणाली में कई कमियां हैं जिनमें सुधार करना बहुत जरूरी है।यदि हमें तेज गति से आर्थिक विकास करना है तो हमें अपनी स्कूल शिक्षा व्यवस्था बेहतर स्तर की बनानी ही होगी। इसके लिए मिडल स्तर के ऊपर के स्कूल छात्रों को वास्तविक जीवन से परिचय करवाइए। उन्हें हवा-हवाई कथाएं न सुनाएं। उन्हें किसी भी तरह की आसमानी किताब न पढ़ाएं। उन्हें जीवन जीना सिखाएं। प्रैक्टिकल बनाएं, ताकि आने वाली पीढियों में एक समझदार एवं सभ्य समाज का निर्माण हो सके। याद रहे कि सांस्कृतिक शिक्षा भी जरूरी है ताकि लोग नैतिक बनें। परंतु यह नैतिकता उनकी अपनी हो, उनके अंदर से आई हो। शिक्षा हमें अपने परिवार, समाज, रीति-रिवाजों, संस्कारों, मूल्यों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि व हमारे इतिहास आदि से परिचित करवाती है। शिक्षा हमें नैतिकता सिखा कर, हमारे कत्तव्यों के बारे में बताकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में हमारी मदद करती है।

आप का नजरीया

हिमाचली कलाकार का हक

अंततः हिमाचल ने अपने शून्य से अर्थ खोजने शुरू किए, तो दागदार होने की वजह भी मिल गई। दरअसल हम मूल प्रश्नों को आगे धकेलते रहे हैं और एक संकीर्णता का माहौल हमारा हालचाल पूछने लगा है। अब इन्हीं धाराओं में बहते कई भीगे हुए प्रश्न मिल जाएंगे, तो रिवायत बदलने की इच्छाशक्ति पैदा करनी होगी। बहरहाल यहां जिक्र शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया का जो शून्यकाल में हिमाचली कलाकारों को मंचों पर मिल रही शून्यता का सवाल उठा रहे हैं। यह कोई नई बहस नहीं और न ही ऐसा तथ्य है जिससे हिमाचली व्यवस्था अनभिज्ञ हो, लेकिन विडंबना यह कि हमारी महफिल के नगीने स्थानीय कलाकार नहीं बने। विधायक पठानिया ने सांस्कृतिक समारोहों में हिमाचली कलाकार के अधिकार की बात उठाते हुए यह मांग रखी है कि संस्कृति के अपने दरवाजे अपने ही घर में तंग नहीं होने चाहिएं, मगर हकीकत यह है कि सारा मनोरंजन अफरा-तफरी में चल रहा है। ऐसी सूचनाएं हैं कि पंजाब के ही एक गायक ने पिछले साल से अब तक कुछ कार्यक्रमों में सवा करोड़ बटोर लिए। यह इसलिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के हाथों में ताली बजाने की खुजली सिर्फ किसी बाहरी कलाकार को बुला कर ही हटती है। अब तो ऐसे भी समारोह होने लगे हैं, जहां सांस्कृतिक कारणों के बजाय नेताओं की हस्ती के खातिर ढोल-नगाड़े बजने लगे हैं। हमने बार-बार लिखा और उस वक्त लिखा था, जब कुल्लू के मंच पर ही ठाकुर दास राठी को समय नहीं मिला था। हमने उस चैक के पीछे भी लिखा जिसकी मोटी राशि किसी बाहरी कलाकार के नाम हुई थी। हम वर्षों से लिख रहे हैं कि सांस्कृतिक समारोहों व तमाम मेलों के आयोजन के लिए एक मेला विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। प्रदेश के मेलों और सांस्कृतिक समारोहों का वर्गीकरण करते हुए इनसे जुड़ी आर्थिकी का संरक्षण जरूरी है। प्रदेश में छोटे-बड़े मेलों, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समारोहों को जोडक़र देखें तो हर साल पांच से सात सौ करोड़ का व्यापार होता है। ये मेले बिखरे हुए हैं। कब कोई सियासी फैसला इन्हें जिला से राज्य और राज्य से अंतरराष्ट्रीय नाम से अलंकृत कर दे, कोई नहीं जानता। जाहिर है अब मेलों के आयोजन के लिए नए व बड़े स्थान चाहिएं, सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन को स्थायी मंच चाहिएं तथा कलाकारों के चयन की एक पद्धति चाहिए। अगर मेला प्राधिकरण को आय-व्यय के हिसाब से वार्षिक कैलेंडर बनाने को प्रेरित किया जाए, तो इसका लाभ पर्यटन उद्योग को भी होगा। पूरे प्रदेश में इस तरह दो-ढाई सौ मेला ग्राउंड विकसित होंगे तथा अधोसंरचना निर्माण में भी भूमिका का विस्तार होगा। इतना ही नहीं, मेला विकास प्राधिकरण के मार्फत पुस्तक, व्यापार, औद्योगिक, फूड, पशु तथा आधुनिक तकनीक के प्रसार में विविध मेलों का आयोजन हो सकता है। मेलों के मार्फत पारंपरिक छिंजों के आयोजन से कुश्ती प्रशिक्षण के कई केंद्र विकसित हो सकते हैं। प्रदेश के ट्राइबल मेलों के अलावा हरियाणा की तर्ज पर सूरजकुंड सरीखे मेलों के आयोजन की पृष्ठभूमि चंडीगढ़ के समीप लगते इलाकों में विकसित की जा सकती है।

राजस्थान का किसान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आदर्श बने : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

बीकानेर (हिंस) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान देश एवं प्रदेश की आत्मा है अगर किसान विकसित होगा तो देश-प्रदेश विकसित एवं खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सपना सिर्फ *कृषि विकास* ही नहीं *कृषि गौरव* है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आदर्श बने। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़े जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें। शर्मा बुधवार को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी को राजस्थान दिवस तथा भारतीय नववर्ष 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है तथा प्रदेशवासी धूमधाम से राजस्थान दिवस मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान को समर्पित है। किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं। किसानों की मेहनत से ही भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है तथा विश्व में हम एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सूरज की तपती धूप, कड़ाके की सर्दी तथा बारिश की बौछार में भी खेतों में खड़े रहकर सिंचाई करते हैं और रखवाली करते हैं। किसानों का यह त्याग और समर्पण अप्रतिम है। आज बीकानेर में हुए किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान हस्तान्तरण किया गया। साथ ही, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि एवं मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा भी बढ़ाया गया है। कार्यक्रम में पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या बढाकर 200 किए जाने तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती करवाए जाने पर 30 हजार की प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए गए। पीएमएफएमई योजना के तीन एफपीओ को अनुदान के तथा एक एफपीओ को शेयर मनी के चैक वितरण किए गए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसान हित पहली प्राथमिकता है। हमनें अपने पहले ही वर्ष में किसान सम्मान निधि में सहायता राशि को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार किया जिसे अब बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना के तहत नि:शुल्क औषधियां और टीके उपलब्ध कराना, मोबाइल वेटनरी सेवा नंबर 1962 प्रारंभ करने, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत लगभग 34 हजार पात्र गोपालकों के ऋण स्वीकृती सहित विभिन्न निर्णयों से पशुपालकों को राहत दी जा रही है। इस वर्ष के बजट में भी बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम) का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी खोलने जैसे प्रावधानों से किसान समृद्ध बनेंगे। शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभाति समझते हैं। इसीलिए हम किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली-पानी की प्राथमिकता पर काम करते हुए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान में 35 हजार करोड़ के एमओयू किए है। राज्य सरकार के ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णयों से किसानों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि गत सरकार में कई पेपरलीक हुए थे, उन प्रकरणों में लिप्त दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। हमारे 15 माह के कार्यकाल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आह्वान किया कि वे मेहनत करे। हम निरंतर भर्तियां तथा नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के सपनों को साकार करेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी विचार रखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादन संगठन मार्गदर्शिका का विमोचन किया तथा लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सफल एफपीओ पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में एफपीओ के मॉडल के रूप में बनाए गए एफपीओ ट्री नवाचार को सराहा। इस दौरान राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, ताराचन्द सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, जेठानंद व्यास सहित बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसान जुड़े।

बजट : पंजाब में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना

गांवों में घरों पर लगेगी स्ट्रीट लाइट

चंडीगढ़ (हिंस) पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बुधवार को सदन में पेश बजट में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू करने का एलान किया है। सरकार अब पंजाब के गांवों में स्ट्रीट लाइटें खंभों की बजाए घरों की छतों पर लगाई जाएंगी। इस लाइट का कनेक्शन घर की लाइट के साथ होगा और इसका खर्च सरकार वहन करेगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सदन में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना शुरू करने का एलान करते हुए कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली क्षेत्र में 7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब *मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना* के तहत 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। इन स्ट्रीट लाइट के लिए खंभे नहीं लगाए जाएंगे। इन्हें लोगों के घरों की छत पर लगाया जाएगा। इन स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन लोगों के घरों में लगे मीटरों के साथ होगा। इस स्ट्रीट लाइट का बिल सरकार वहन करेगी। इसका खर्च संबंधित व्यक्ति के बिल से कम कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस योजना के लागू करने के लिए 115 करोड़ रुपए का बजट रखा है। चीमा ने कहा कि पहले पंजाब को बत्ती गुल पंजाब कहा जाता था, अब पंजाब को बत्ती फुल पंजाब कहा जाता है। राज्य के 166 शहरों व कस्बों में भी स्ट्रीट लाइटों का रिव्यू किया जाएगा। 166 कस्बों में साफ सफाई, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें प्रदान के लिए 225 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 14 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

जयपुर (हिंस) ग्रेटर निगम की सतर्कता शाखा ने बुधवार को झोटवाड़ा जोन की स्वास्थ्य शाखा द्वारा कनकपुरा रेलवे स्टेशन, सिरसी रोड से सिंवार मोड़ तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले 14 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर 23500 रुपए का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया। उक्त कार्रवाई में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक वीरेंद्र कुमार, नीलम कुमारी शर्मा स्वास्थ्य निरीक्षक राजेंद्र कुमार, तेजपाल वैद्य मौजूद रहे। उपायुक्त झोटवाड़ा जोन मनीषा यादव ने बताया कि सतर्कता शाखा की अस्थाई टीम एवं झोटवाड़ा जोन स्वास्थ्य शाखा द्वारा कनकपुरा रेलवे स्टेशन, सिरसी रोड से सिंवार मोड़ तक अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सिंवार मोड़ पर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों को समझाइश करने पर अपनी थड़ियां क्रेन द्वारा स्वत: ही हटा ली साथ ही स्वास्थ्य शाखा ने गंदगी करने वाले एवं अस्थाई अतिक्रमण करने वाले एवं प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों की प्लास्टिक जब्त कर 14 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर 23 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

बजट : पंजाब के दलितों का पीएससीएफसी का कर्ज होगा माफ

राज्य की जेलों में लगाए जाएंगे हाईटैक कैमरे

चंडीगढ़ (हिंस) पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य के दलितों के पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम (पीएससीपीएफ) से लिए गए लोन को माफ करने का एलान किया है। 31 मार्च 2020 से पहले के 4650 कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने साथ ही पंजाब की जेलों में एआई आधारित कैमरे लगाने की बात कही है। बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सदन में बजट पेश करने के दौरान कहा कि सरकार ने राज्य के दलितों के पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्तीय निगम से लिए गए लोन को माफ करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 से पहले के 4650 र्जदारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में होने वाली घटनाओं पर नकेल डालने के लिए सरकार ने एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जेल विभाग के लिए 11 हजार 560 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा जेलों एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। 2,200 से कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया है। जेलों के नवीनीकरण व अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे पुलिस लाइनों के निर्माण व अन्य चीजों पर पैसा खर्च होगा। ज्यूडिशियल सिस्टम को बढ़ाने के लिए डेराबस्सी, खन्ना व पात?ा में 132 करोड़ से ज्यूडिशियल कांप्लेक्स बनाए जाएंगे। पुल व सड़कों के निर्माण पर काफी अच्छा काम किया जा रहा है। राज्य की 2718 किलोमीटर सड़कों के लिए 855 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पुलों के काम के लिए 155 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव है। पांच बड़े पुलों के लिए 190 करोड़ रुपए और 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए 17,925 करोड़ बजट रखा वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मिशन समर्थ के तहत 14 लाख स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है। प्री प्राइमरी व 12वीं तक मेगा पीटीएम आयोजित की गईं। इसमें 21 लाख अभिभावकों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेड मास्टर व अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों से ट्रेनिंग दिलाई है। इससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। साल 2025-26 के लिए 17,925 करोड़ का बजट रखा है। 425 स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदला जा रहा है। पंजाब यंग एंटर प्रेन्योरशिप जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। 4098 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनक्लूसिव विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल व लर्निंग सुविधा प्रोग्राम पर जोर दिया जाएगा। बजट रूसा स्कीम 199 करोड़, बुनियादी सुविधा के लिए 160 करोड़ का बजट रखा गया है।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में घट रही विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की है कमी

विधानसभा में इनेलो व कांग्रेस ने पेश किया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चंडीगढ़ (हिंस) हरियाणा के राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी और घटती विद्यार्थियों की संख्या के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा सदन में गूंजा। विपक्ष ने राजकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और आरोप लगाए कि राजकीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया कि राजकीय स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ाया जा रहा है। निपुण कार्यक्रम की विदेशों तक धूम है, अफ्रीका सहित 18 देश निपुण कार्यक्रम को जानने पहुंच हैं। बुधवार को कांग्रेस ने राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ बुनियादी सुविधाओं, जिनमें पीने के पानी व शौचालय की कमियों बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा। वहीं इनेलो ने चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले की मनमानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नायब सरकार को घेरते हुए मुद्दा उठाया कि सरकार राजकीय स्कूलों में बदलाव के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन 2024 की वार्षिकी रिपोर्ट में हरियाणा के बच्चे पढ़ाई में पड़ोसी राज्य पंजाब व हिमाचल से भी पीछे हैं। इसके साथ ही 1100 स्कूलों में शिक्षक व विद्यार्थी नहीं हैं। 71 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं हैं। 16 फीसदी वर्किंग नहीं हैं। मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है, 20 फीसदी स्कूलों में शौचालय नहीं है, 3 फीसदी में लड़कियों के शौचालयों की कमी है। 14 फीसदी स्कूलों में पीने के पानी की कमी है। अरोड़ा ने शिक्षा मंत्री को घेरते हुए जवाब मांगा कि जब मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर कैसे दे पाएंगे। वहीं पिहोवा से कांग्रेस विधायक मनदीप चट्ठा और फतेहाबाद विधायक बलवान दौलतपुरिया ने शिक्षकों की कमी, कक्षा-कक्ष और भवनों की जर्जर हालत का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने शिक्षकों की कमी के साथ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल फीस और किताबों में मनमानी कर रही है। सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जिस किताब की कीमत 50 रुपए है, उसे प्राइवेट स्कूल संचालक 150 रुपए में बेच रहे हैं और मनमर्जी की फीस वसूल रहे हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीब आदमी शिक्षा से दूर हो रहा है, क्योंकि राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ कोई सुविधा नहीं है। मजबूरी में लोग कर्जा लेकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया कि पीजीटी के कुल 4780 पदों को भरने बारे मांग पत्र 05 जुलाई 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। इस मांग पत्र के आधार पर वर्ष 2025 में 1704 पदों की सिफारिशें विभाग को प्रापत हो चुकी हैं तथा नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही पीजीटी पदोन्नति कोटे के 4550 रिक्त पदों को भरने बारे पदोन्नति मामले आमंत्रित किए जा चुके हैं। 3427 पदों को एचकेआरएन के माध्यम से भेजा जाएगा। पीआरटी मेवात कैडर के 1456 पदों को भरा जा चुका है और 7110 पद एचकेआरएन के जरिये नियुक्त किए गए हैं।

संभल में सड़कों-छतों पर नहीं पढ़ सकेंगे जुमा अलविदा और ईद की नमाज : एएसपी श्रीशचंद्र

संभल (हिंस) जिले में जुमा अलविदा और ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। ना हीं छतों पर नमाज अदा होगी। लाउडस्पीकर को लेकर भी सरकार के गाइडलाइन का पालन करना होगा। यह कहना है कि अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्रीशचंद्र का है। सदर कोतवाली में बुधवार को एएसपी, एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में अमन कमेटी की बैठक हुई। इसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। एएसपी ने कहा कि शांति समिति की बैठक में सभी धर्मों के लोगों के साथ की गई। इसमें स्पष्ट रूप से अवगत और सुनिश्चित कराया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। परिसर के बाहर सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं की होगी। साथ ही बिजली, पानी की समस्या से भी अवगत कराया गया, जिसे समय रहते दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने समय अनुसार लाउडस्पीकर की मांग की थी, उसके संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया। जोनल व सेक्टर व्यवस्था पूर्व की तरह लागू है। पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों के साथ ही छतों पर नमाज अदा नहीं हो। उपजिलाधिकारी डॉ. वंदना मिश्रा ने कहा कि शांति समिति की बैठक में जिन-जिन लोगों ने बिजली, पानी आदि की समस्या बताई थी। संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान कर लिया जाए। लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी गई है।

सड़क हादसे में दंपती सहित तीन की मौत

जोधपुर (हिंस) फलोदी के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में दंपती सहित तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं डेढ़ साल की मासूम सहित दो लोग घायल हैं। कार सवार जोधपुर एम्स से बच्ची का इलाज करवा कर लौट रहे थे। एक्सीडेंट चाबा गांव के पास मंगलवार रात को हुआ। एक्सीडेंट में कार पूरी तरह से पिचक गई थी। घायलों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार हादसे में भोजाकोर के ग्रेड सेकेंड टीचर गणेश राम (32) पुत्र रामूराम और उनकी पत्नी ममता की मौत हो गई। वहीं सीनियर स्कूल के एलडीसी भादरा, हनुमानगढ़ निवासी अजय कुमार (35) ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। गणेश और ममता की डेढ़ साल की बेटी मनस्वी शेरगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं गणेशराम के दोस्त और स्कूल लेक्चरर बरजासर बीकानेर निवासी गिरधारीराम (30) गंभीर घायल हैं। उन्हें शेरगढ़ से जोधपुर रेफर किया गया है। सभी लोग गणेशराम और ममता की बेटी मनस्वी का इलाज कराने के लिए मंगलवार को जोधपुर एम्स आए थे। शाम करीब सात बजे वे जोधपुर से राजमथाई जैसलमेर के लिए रवाना हुए थे। रात करीब दस बजे चाबा गांव के नजदीक सामने से आ रहे डंपर ने कार को टक्कर मार दी। तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों टीचर और क्लर्क जैसलमेर के राजमथाई में अलग-अलग जगह पोस्टेड थे। पुलिस का कहना है कि आरोपित डंपर चालक की तलाश की जा रही है। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो सरकारी क्लर्क अजय की कार थी। वो ही ड्राइव भी कर रहे थे। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से भाग निकला। वहीं, घटना स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और किसी तरह पुलिस ने लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। इनमें बच्ची को मामूली चोट लगी है।

राहुल गांधी का कोई विजन नही हैं, वह छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं : बृजेश पाठक

कानपुर (हिंस) विपक्ष केवल जाति और धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है। उनका अभी भी इटली का मोह नहीं छूट रहा है। शायद इसीलिए वह छुट्टियां बिताने अपनी नानी के घर चले जाते हैं। प्रयागराज में इतना भव्य महाकुंभ का सफलतापूर्वक हुए आयोजन को लेकर विपक्ष परेशान है। अखिलेश यादव के पेट में सत्ता हासिल करने का कीड़ा है। यह बातें बुधवार को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही। प्रदेश में योगी सरकार को आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किये जा रहे हैं। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक शहर पहुंचे। जहांबीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन के आठ वर्षों के सफर को पूरा होने पर बधाई दी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने अन्य विभागों की प्रदर्शनी

का भी अवलोकन किया, जहां विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने एक प्रभावी मतदाता सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए उत्साहित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दल जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और प्रदेश में विकास के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनावों में भारी जीत हासिल करने का आह्वान किया।

पति व ससुर की गिरफ्तारी के बाद उठाया विवाहिता का शव

जोधपुर (हिंस) माता का थान थाना क्षेत्र में फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाली विवाहिता का शव परिजनों ने बुधवार को ले लिया। मामले में पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। इसमें लेकर दहेज हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति व ससुर को हिरासत में लिया है। माता का थान एसएचओ भंवरसिंह जाखड़ ने बताया कि बनाड़ के नांदड़ा खुर्द में करणी विहार कॉलोनी निवासी हनुमान प्रसाद गौड़ पुत्र बाबूलाल की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया कि उसकी बहन ममता की शादी वर्ष 2021 में माता का थान के निकटवर्ती मदेरणा कॉलोनी निवासी वासुदेव गौड़ के साथ हुई थी। इस विवाह से ममता के एक बेटा है लेकिन, ससुर सुरेश, सास लक्ष्मी, जेठ विमल व जेठानी पुष्पा लंबे समय से ममता को प्रताड़ित कर रहे थे।

पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पप्पू यादव ने अमित शाह को लिखा पत्र

पूर्णिया (हिंस) पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना उच्च न्यायालय की दूसरी न्यायपीठ (खंडपीठ) को पूर्णिया में स्थापित करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कोशी-सीमांचल क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने में आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पप्पू यादव ने अपने पत्र में बताया कि जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के 2000 के फैसले (रिट याचिका संख्या-379) के अनुसार, उच्च न्यायालय की दूसरी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार और राज्यपाल की सहमति जरूरी है। हालांकि, अभी तक पूर्णिया में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। पप्पू यादव ने पत्र में लिखा कि पूर्णिया और कोशी-सीमांचल से पटना की दूरी काफी अधिक है। गरीब लोगों के लिए बार-बार पटना आकर केस लड़ना मुश्किल होता है। पटना हाईकोर्ट पर मुकदमों का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे न्याय में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया को *दूसरा दार्जिलिंग* कहा जाता है और यहां की जलवायु भी अनुकूल है, इसलिए यहां न्यायपीठ स्थापित करना उचित होगा। गौरतलब है कि पप्पू यादव इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने पहले बिहार सरकार के विधि विभाग को पत्र लिखा था, जिसके बाद विभाग ने पटना हाईकोर्ट के निबंधक (प्रशासन) को इस पर कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसके अलावा, उन्होंने बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात कर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा था। अपने पत्र में पप्पू यादव ने अमित शाह से अनुरोध किया है कि बिहार सरकार को पूर्णिया में न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय को भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम कोशी-सीमांचल के लोगों के लिए न्याय सुलभ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

स्वतंत्र भारत के संघर्ष से जुड़ा है बिहार दिवस का इतिहास : चक्रपाणि

भागलपुर (हिंस)। टीएनबी विधि महाविद्यालय भागलपुर के सभागार में बुधवार को बिहार दिवस के समापन समारोह का आयोजन संस्कृति परिषद द्वारा किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु थे। इस अवसर पर निबंध, कविता एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में निबंध में स्मृति सिंह, पेंटिंग में अभिलाष कुमार और कविता में अभिजीत कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों के बीच पदक एवं प्रमाण पत्र वितरण किया गया। अवसर पर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि समृद्ध इतिहास और संस्कृति का जश्न मनाया जाता है। राज्य की जीवंत विरासत और

राष्ट्र के लिए इसके योगदान को प्रदर्शित करते हैं। बिहार दिवस का इतिहास स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बिहार के प्रमुख नेताओं में जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्रीकृष्ण सिंह, वीर कुवर सिंह, मौलाना मजरुल हक, मोहम्मद इमाम आदि शामिल हैं। बिहार ने चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने और व्यापार को आसानी से बढ़ावा देने का नीति बनाया। राज्य के युवाओं को परिवर्तन के एजेंट और आने वाले वर्षों में राज्य की प्रगति को चलाने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रतियोगिता प्रमाण पत्र एवं पदक के वितरण में टीएनबी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रो धीरज कुमार, डॉ. रमाशंकर, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉ. बबीता कुमारी, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर सुजाता कुमारी, डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, प्रोफेसर बिन्नी एवं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार एवं छात्र, छात्राएं उपस्थित थे।

बंद हुई मध्यम और दीर्घ अवधि वाली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लघु अवधि के लिए जमा करा सकेंगे सोना

नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 साल से चलाई जा रही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (जीएमएस) से बंद कर दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा नामित कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर (सीपीटीसी) या सरकार द्वारा नामित बैंक की शाखाओं पर से मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि वाली स्कीम में सोने को जमा नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के परफॉर्मेंस और बाजार की स्थितियों को देखते हुए लिया है।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत 15 सितंबर 2015 को हुई थी। इसके तहत लोग अपने घर में पड़े सोने को अपनी इच्छा के अनुसार 1 से 3 साल की शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट (एसटीबीडी), 5 से 7 साल की मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (एमटीजीडी) या 12 से 15 साल की लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट (एलटीजीडी) में जमा कर सकते थे। सोना जमा करने पर जमाकर्ताओं को सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड इश्यू किया जाता था। ये बॉन्ड 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के होते थे। सोना जमा करने के बाद जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान किया जाता था। ब्याज की राशि सोना जमा करते वक्त उसकी मार्केट प्राइस के आधार पर तय की जाती थी।

जानकारों का कहना है कि इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे सरकार का इरादा सोने के आयात में कमी लाने का था। भारत में हर साल करीब 800 टन सोने की खपत होती है, जबकि भारतीय खदानों से सालाना 1 टन सोने का ही उत्पादन हो पता है। इस तरह भारत में सोने की जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर सोने का आयात करना पड़ता है, जिसके कारण देश के आयात बिल में तो बढ़ोतरी होती ही है, विदेशी मुद्रा भी बड़े पैमाने पर खर्च होती है।

बताया जाता है कि केंद्र सरकार की ओर से सोचा गया था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू करने से लोग घर में पड़े सोने को जमा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे उन्हें सोने की सुरक्षा की चिंता भी नहीं करनी होगी और उसके एवज में उन्हें इंटरेस्ट के रूप में अच्छी कमाई भी होगी।

न्यूज ब्रीफ

सैमसंग से सरकार ने मांगे 5154 करोड़ रुपए, सैमसंग पर टैरिफ से बचने कलपुर्जों के आयात में की हेराफेरी का आरोप

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सैमसंग व उसके अधिकारियों से 60.1 करोड़ डॉलर (करीब 5,154 करोड़ रुपये) मांगे हैं। सैमसंग पर आरोप है कि उसने देश में प्रमुख दूरसंचार उपकरणों के आयात पर टैरिफ से बचने के लिए हेराफेरी की थी। यह मांग भारत में सैमसंग के पिछले साल के 95.5 करोड़ डॉलर के मुनाफे का बड़ा हिस्सा है। कंपनी नेटवर्क विभाग के जरिये दूरसंचार उपकरणों का आयात करती है। कंपनी को मोबाइल टावरों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन कलपुर्जे पर 10 या 20 फीसदी के टैरिफ से बचने के लिए आयात को गलत तरीके से वर्गीकृत करने पर 2023 में चेतावनी दी गई थी। सैमसंग ने कलपुर्जों का आयात कर जियो को बेचा। सैमसंग की जांच 2021 में तब शुरू हुई जब कर निरीक्षकों ने मुंबई व गुरुग्राम में कार्यालयों की तलाशी में दस्तावेज, ईमेल व उपकरण जब्त किए। सीमा शुल्क आयुक्त ने आदेश में कहा, सैमसंग ने कानूनों का उल्लंघन किया है और सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। लाभ बढ़ाने के लिए सैमसंग ने सरकारी खजाने को चूना लगाया। कंपनी ने व्यावसायिक नैतिकताओं और उद्योग मानकों का उल्लंघन किया। सैमसंग विवाद रिमोट रेडियो हेड के आयात पर केंद्रित है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट है जो छोटे आउटडोर मॉड्यूल में संलग्न होता है।

पूर्व ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त

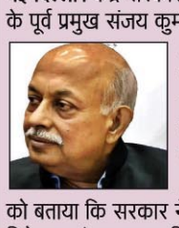

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। संजय कुमार मिश्रा को सचिव स्तर का दर्जा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकार ने मंगलवार को ईडी के पूर्व निदेशक संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दे दी। उन्हें सचिव स्तर का दर्जा दिया है। मिश्रा 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी हैं। उन्होंने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय में लंबा कार्यकाल बिताया है। अब वे जांच एजेंसी की भूमिका से हटकर नीति निर्धारण की भूमिका में आ गए हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र संस्था है, जो प्रधानमंत्री को आर्थिक और उससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है। उल्लेखनीय है कि मिश्रा को सबसे पहले 2018 में ईडी प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें केंद्र द्वारा कई बार सेवा विस्तार दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान ईडी को विजय माल्या, नीरव मोदी और हथियार डीलर संजय भंडारी जैसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली। ईडी ने मिश्रा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों से जुड़ी जांच शुरू की।

भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि, मंत्री बघेल ने संसद में किया खुलासा, वैश्विक उत्पादन में देश की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली। भारत का दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 63.56 प्रतिशत तक उछाल दिखाया है। 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से यह उत्पादन 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन के निकट आ पहुंचा है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत है। यहाँ खास बात यह है कि भारत के दूध का उत्पादन विश्व में औसत से भी अधिक बढ़ रहा है। मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने संसद में बताया कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भारत में पिछले एक दशक में 48 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 के दौरान 471 ग्राम/व्यक्ति/दिन से भी अधिक हो गई है। विश्व में इस संदर्भ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 322 ग्राम/व्यक्ति/दिन है। भारत दूध उत्पादन में अब वैश्विक स्तर पर द्रुत विकास कर चुका है और यह अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। मंत्री ने बताया कि दूध एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी दी। केंद्र के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को पूरे देश में लागू किया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों द्वारा दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए की गई पहल को सफल बनाया जा सके।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत एशिया में भी तेजी का रुख

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान तेजी का रुख बना रहा। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजारों में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एशियाई बाजारों में भी आमतौर पर मजबूती का रुख बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,776.65 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.46 प्रतिशत उछल कर 18,271.86 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी फिलहाल 0.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 42,636.64 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजारों में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,663.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 1.06 प्रतिशत उछल कर 8,108.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 257.13 अंक यानी 1.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,109.79 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में भी आमतौर पर तेजी का रुख बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 8 के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बना हुआ है। एशियाई बाजारों में इकलौता ताइवान वेटेड इंडेक्स फिलहाल 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,251.32 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.11 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,705 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,967.18 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स ने बड़ी छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 219.27 अंक यानी 3.52 प्रतिशत उछल कर 6,454.89 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 0.87 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,638.69 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा निक्केई इंडेक्स 254.79 अंक यानी 0.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 38,035.33 अंक के स्तर पर, सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.60 प्रतिशत की मजबूती के साथ 1,192.08 अंक के स्तर पर, हैंग सेंग इंडेक्स 0.22 प्रतिशत की छलांग लगा कर 23,394.94 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,375.97 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

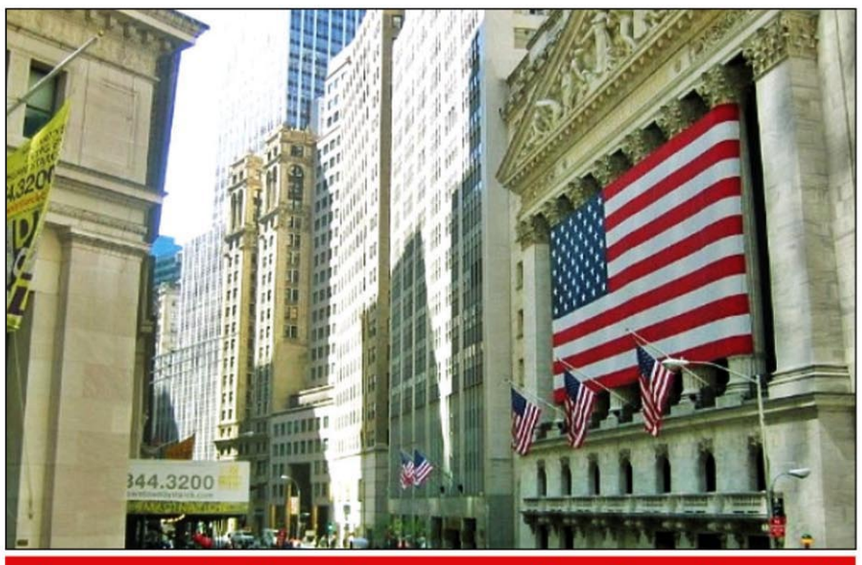

लोकसभा ने मंजूर किया फायनेंस बिल वित्त मंत्री ने दी टैक्सपेयर्स को राहत

नई दिल्ली। लोकसभा ने भारतीय सरकार के फायनेंस बिल 2025 को पास कर दिया, जिसमें 35 सरकारी संशोधन शामिल हैं। यह फाइनेंस बिल केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रपोजल को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बिल को समर्थन दिया और बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की घोषणा की। ईवी बैटरी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कस्टम्स ड्यूटी में छूट भी दी गई फाइनेंस बिल 2025 पर हुई डिबेट में वित्त मंत्री ने टैरिफ रेशनलाइजेशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए बदलावों को बताया। इसके साथ ही, ईवी बैटरी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कस्टम्स ड्यूटी में छूट भी दी गई है। बजट को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे अब राज्यसभा में भी चर्चा के लिए रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने आम बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.4 फीसदी रखा गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 में 4.8 फीसदी था। केंद्रीय बजट 2025-26 में खपत को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इससे मिडिल क्लास के हाथ में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे। बजट में नेट मार्केट बॉरोइंग 11.54 लाख करोड़ रुपये तय की गई है। बाकी का फंड स्मॉल सेविंग्स स्कीम से आएगा।

90 लाख करदाताओं ने फाइल किया अपडेटेड आईटीआर

नई दिल्ली

वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम की सफलता को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय ने कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन योजना को मंजूरी दी है, जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए एमडीआर शून्य किया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का कर चुकाया गया है। सरकार ने फाइनेंस बिल, 2025 के जरिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को संबंधित असेसमेंट ईयर से चार साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.979 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर चुकाए गए।

असेसमेंट ईयर 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमश: 4.007 मिलियन और 1.724 मिलियन अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और अतिरिक्त 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये कर चुकाए गए। एक दूसरे सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी - पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को यूपीआई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप उठाए गए हैं। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। ग्राहकों, व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान उद्योग द्वारा किए गए व्यय को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के जरिए वसूला जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक शुल्क है जिसे व्यापारियों और अन्य व्यवसायों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को देना होगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एमडीआर आमतौर पर लेनदेन राशि के प्रतिशत के रूप में आता है। आरबीआई के अनुसार, डेबिट कार्ड के लिए सभी कार्ड नेटवर्क पर लेनदेन मूल्य का 0.90 प्रतिशत तक का एमडीआर लागू है। एनपीसीआई के अनुसार, यूपीआई पी2एम (पर्सन टू मर्चेंट) लेनदेन के लिए 0.30 प्रतिशत तक का एमडीआर लागू है।

सरकार को मिला 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व

ओरिक्स इंडिया को 300 करोड़ का मिला इक्विटी निवेश

ओरिक्स कॉर्पोरेशन ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी ओरिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में विकास और विस्तार करने के लिए 300 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है जो भारत के तेजी से बढ़ते मोबिलटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों के लिए है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह निवेश भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने और ओरिक्स इंडिया के लीजिंग, मोबिलिटी और वित्तीय सेवा व्यवसायों के विस्तार में तेजी लाने के उसके दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इसी वित्त वर्ष जापान से आगे निकलने को तैयार

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीडीपी के दृष्टिकोण से भारत अब वर्तमान में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जापान के करीब पहुंच रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में दोगुने से भी अधिक वृद्धि की है, जो वर्ष 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में अनुमानित रूप में 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले दस सालों में 105 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि जापान की जीडीपी स्थिर बनी हुई है। यदि भारत इसी दर से आगे बढ़ता रहा, तो 2027 की दूसरी तिमाही तक 4.9 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ भार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। भारतीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई नीतियों की घोषणा की है, जिनमें निवेश को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और नौकरियों के अवसर में सुधार करना शामिल है। इन कदमों के साथ, भारत अंतरराष्ट्रीय अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

वित्तीय समावेश में अनपेक्षित बाधाओं से सावधानी की जरूरत : आरबीआई गवर्नर

मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि विनियमनों से वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में अनपेक्षित बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के यहां आयोजित कार्यक्रम में मल्होत्रा ने कहा कि नीति निर्माताओं को भी सावधान रहना चाहिए और अपने उपायों को लेकर अति उत्साही नहीं होना चाहिए।

मल्होत्रा ने कहा कि भारत ने वित्तीय समावेश की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनियमन वित्तीय समावेश में अनपेक्षित बाधाएं उत्पन्न न करें। हमें उचित संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्राहकों के अधिकारों और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।

गवर्नर ने कहा, जबकि हम अपनी वित्तीय प्रणालियों को धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें नीति निर्माताओं के रूप में यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे उपाय अति उत्साही न हों और वैध गतिविधियों तथा निवेशों को बाधित न करें। गवर्नर ने संतुलित विनियमन की वकालत करते हुए कहा कि जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी होगा तथा लोगों व व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। मल्होत्रा ने कहा कि हम अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन भावनात्मक मुद्दों पर गौर करते हुए, मल्होत्रा ने देश में नए गोपनीयता कानून को लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही, गवर्नर ने कहा कि वित्तीय संस्थाओं एवं वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यात्रा नियम को प्रौद्योगिकी तटस्थ बनाने में मदद मिलेगी।

एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाई एक नई यात्रा नीति

मुंबई। भारतीय विमानन कंपनी एअर इंडिया ने अपनी कर्मचारियों के लिए एक नई यात्रा नीति का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनी के सीईओ, शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ कमांडर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। यह नीति अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इस नीति के अनुसार, शीर्ष प्रबंधन के लिए यह विवरण 1 अप्रैल से लागू होगा, जबकि वरिष्ठ कमांडरों के लिए यह 1 जून से प्रभावशाली होगी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का मकसद है कंपनी की प्रीमियम सीटें उपलब्ध रखना ताकि ग्राहकों को सुविधा मिले। नई एअर इंडिया की इस सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण अवसर है जो कंपनी की प्रगतिशील सोच और ग्राहक-केंद्रित संस्कृति को दर्शाती है। इसके साथ ही नीति में अपग्रेड विकल्प भी शामिल है जो ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करता है।

फिल सिमंस 2027 वनडे विश्व कप तक बने रहेंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच

ढाका

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने मंगलवार को घोषणा की कि वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज फिल सिमंस को पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में 2027 आईसीसी वनडे विश्व कप तक बनाए रखने का फैसला किया गया है। 61 वर्षीय सिमंस पहले ही बीसीबी के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक अनुबंधित थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक बांग्लादेश टीम के साथ काम किया और इस दौरान दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में टीम का मार्गदर्शन किया।

फिल सिमंस ने इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, बांग्लादेश क्रिकेट के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर पाकर मैं बहुत उत्साहित हूं। इस टीम में जबरदस्त प्रतिभा है और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर बेहतरीन उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आने वाले सफर को लेकर मैं काफी आशान्वित हूं।

उन्होंने आगे कहा, इस टीम में कुछ असाधारण खिलाड़ी हैं, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे पहले ही मिल चुका है। उनकी क्षमता और खेल के प्रति जुनून मुझे हर दिन प्रेरित करता है। हम मिलकर बांग्लादेश क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और कुछ खास बना सकते हैं।

अपनी अब तक की यात्रा पर बात करते हुए सिमंस ने कहा, पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश टीम के साथ मेरा समय बेहद संतोषजनक रहा है। इस टीम के खिलाड़ियों का समर्पण, ऊर्जा और प्रतिभा काफी प्रभावशाली है। मैं उत्साहित हूं कि इन खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाने में योगदान दे सकता हूं।

गौरतलब है कि सिमंस ने 1987 से 1999 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 26 टेस्ट और 143 वनडे खेले थे। उन्होंने 2004 में ज़िम्बाब्वे के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय कोचिंग करियर की शुरुआत की और 2007 से 2015 तक आयरलैंड के कोच रहे। सिमंस को दो बार वेस्टइंडीज का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था और 2016 में उनकी कोचिंग में टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 खिताब जीता था।

न्यूज ब्रीफ

केन्या के स्टार धावक ओमान्याला नेशनल ट्रायल्स में भाग लेंगे

कंपाला। अफ्रीका के सबसे तेज़ धावक और केन्या के स्टार फर्राटा धावक फर्डिनेंड ओमान्याला 29 मार्च, शनिवार को होने वाले युगांडा के तीसरे राष्ट्रीय एथलेटिक्स ट्रायल्स में भाग लेंगे। युगांडा एथलेटिक्स फेडरेशन (यूएएफ) के अध्यक्ष डॉमिनिक ओतुचेट ने मंगलवार को शिन्हुआ को बताया कि ओमान्याला सहित कुल 10 केन्याई धावक इन राष्ट्रीय ट्रायल्स में हिस्सा लेंगे। ओतुचेट ने कहा, हमारे लिए यह खुशी की बात है कि ओमान्याला, जो 100 मीटर में अफ्रीका के सबसे तेज़ धावक हैं और विश्व के शीर्ष 10 धावकों में शामिल हैं, हमारे नेशनल ट्रायल्स की शोभा बढ़ाएंगे। वह पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा और 4×100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ये ट्रायल्स विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, जिनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शामिल है, से पहले खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने में मदद करेंगे। ओमान्याला युगांडा के युवा धावकों को प्रेरित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि ओमान्याला ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा, उन्होंने 2022 अफ्रीकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर और 4×100 मीटर रिले स्पर्धाओं में भी खिताब अपने नाम किया था।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए अर्जेंटीना ने किया सीधा क्वालीफाई

नई दिल्ली। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। मंगलवार (भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह) को खेले गए क्वालीफायर मुकाबले में बोलीविया और उरुग्वे के बीच ड्रॉ होने के बाद अर्जेंटीना को टूर्नामेंट का टिकट मिल गया। अब लियोनेल स्कालोनी की टीम अपने अगले क्वालीफायर मुकाबले में ब्राजील से भिड़ेगी। यह मुकाबला मंगलवार को ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोन्यूमेंटल में खेला जाएगा। इस मैच से पहले ही अर्जेंटीना ने विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगर उरुग्वे यह मैच हार जाता तो अर्जेंटीना को ब्राजील के खिलाफ कम से कम एक अंक की जरूरत होती। हालांकि, बोलीविया और उरुग्वे के गोलरहित ड्रॉ ने अर्जेंटीना की राह आसान कर दी। अपने पिछले क्वालीफायर में उरुग्वे पर 1-0 की जीत के बाद अर्जेंटीना कम से कम इंटर-कॉन्फ़ेडरेशन प्लेऑफ में जगह बनाने की स्थिति में था। वहीं, इस ड्रॉ के बाद बोलीविया 14 मैचों में 14 अंकों के साथ क्वालीफाइंग तालिका में सातवें स्थान पर है। अर्जेंटीना, जिसने 13 मैचों में 28 अंक जुटाए हैं, अब टॉप-6 में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जिससे उसे सीधे विश्व कप में प्रवेश मिल गया है।

गावस्कर ने गंभीर से पूछा, क्या द्रविड़ की तरह पुरस्कार की रकम बांटेंगे

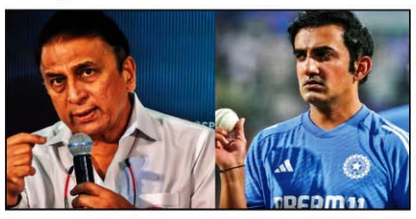

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अब मुख्य कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठाये हैं। गावस्कर ने गंभीर से पूछा है कि क्या वह पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की तरह सहयोगी स्टाफ के बराबर रकम लेने की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे या नहीं। गौरतब है कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 58 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें खिलाड़ियों और मुख्य कोच गौतम गंभीर को तीन-तीन करोड़ रुपये दिये जाएंगे। वहीं सहायक कोच और सहयोगी स्टाफ को 50-50 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई अधिकारियों को 25-25 लाख रुपये मिलेंगे। गावस्कर ने कहा है कि गंभीर से पहले कोच रहे द्रविड़ ने टी-20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद अपने सहयोगी स्टाफ के बराबर नकद पुरस्कार लिया था। वहीं गंभीर ने अभी तक इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। गावस्कर ने कहा, 'आईसीसी टी-20 विश्व कप जीतने के बाद उस समय कोच रहे द्रविड़ ने अपनी टीम के सहयोगी स्टाफ से ज्यादा राशि लेने से मना कर दिया था और कोचिंग स्टाफ को मिलने वाली कुल रकम को सभी के साथ बराबरी से बांटा था पर अभी तक इस मामले में गंभीर की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था।

पैरालंपिक पदक के बिना अधूरा महसूस करती हूं : भाग्यश्री

नई दिल्ली

सच्चे चैंपियन मुश्किल राहों से गुजरते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और जज्बा ही उन्हें खास बनाता है। अनुभवी शॉट पुटर और जैवलिन थ्रोअर भाग्यश्री जाधव ने टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पदक से चूक गईं। अब उनकी नजर लॉस एंजिलिस 2028 पैरालंपिक में देश के लिए पदक जीतने पर टिकी है।

महाराष्ट्र की 37 वर्षीय भाग्यश्री जाधव, जो पेरिस पैरालंपिक में भारत की ध्वजवाहक भी थीं, इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शॉट पुट और जैवलिन थ्रो में दो स्वर्ण पदक जीतकर अपने दमखम का परिचय दिया। एफ-33-34 कैटेगरी (निचले अंगों की अक्षमता) में प्रतिस्पर्धा कर रहीं भाग्यश्री ने बीते डेढ़ साल में तीन इवेंट्स में छह स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं।

उन्होंने शॉट पुट में 7.30 मीटर की थ्रो कर कर्नाटक की मेधा जयंत (4.65 मीटर) को हराया, वहीं भाला फेंक में 13.57 मीटर की दूरी तय कर उत्तर प्रदेश की दीपिका रानी (10.42 मीटर) को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले भी उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में दो स्वर्ण पदक जीते थे।

भाग्यश्री जाधव ने 2017 में पैरा खेलों में कदम रखा और पहली बार पुणे में आयोजित मेयर्स कप में भाग लिया, जहां उन्होंने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। इसके बाद मार्च 2022 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में दो स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत को कई बार गौरवान्वित किया है। 2022 एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने एफ-34 कैटेगरी में 7.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। इसके अलावा 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक और 2021 में दुबई वर्ल्ड कप में कांस्य पदक अपने नाम किया।

भाग्यश्री 2019 के टोक्यो पैरालंपिक में फाइनल में पहुंचकर सातवें स्थान पर रहीं, जबकि पेरिस 2024 पैरालंपिक में पांचवें स्थान पर रहीं। अब उनका एक ही सपना लॉस एंजिलिस 2028 में पदक जीतना है।

भाग्यश्री ने कहा, मैंने हर जगह खुद को साबित किया है, लेकिन जब तक पैरालंपिक पदक नहीं जीतूंगी, तब तक खुद को अधूरा महसूस करूंगी। टोक्यो में मैं सातवें स्थान पर थी, पेरिस में पांचवें स्थान पर रही, लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ देश के लिए पदक जीतना है। भाग्यश्री के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब 2006 में हुए एक बड़े हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। वह कोमा में चली गईं, वेंटिलेटर पर थीं और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें जीवन की नई राह दिखाई। भाग्यश्री बताती हैं कि उनके भाई प्रकाश जाधव कांबले, जो पत्रकार हैं, ने ही उन्हें खेलों में उतरने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, भाई को सुझाव दिया गया था कि मैं पैरा खेलों में अच्छा कर सकती हूं। उनके कहने पर मैंने शॉट पुट और जैवलिन शुरू किया और आज मैं इस मुकाम पर हूं।

एशियन चैंपियनशिपः सुनील कुमार ने 87 किग्रा ग्रीको-रोमन कुश्ती में जीता कांस्य पदक

अम्मान। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने मंगलवार को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको-रोमन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में सुनील ने चीन के जियाविसन हुआंग को हराया। इससे पहले वह सेमीफाइनल में हारकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए थे। 2019 में रजत पदक जीतने वाले सुनील की कोशिश अपनी पुरानी फॉर्म को वापस पाने की है। उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत ताजिकिस्तान के सुखरोब अब्दुलखाएव के खिलाफ दमदार अंदाज में की, जहां उन्होंने दूसरे पीरियड में 10-1 से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि, सेमीफाइनल में ईरान के यासीन यज्दी ने 3-1 से हराकर उनका फाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कांस्य के लिए मुकाबला खेला। सागर ठाकरान की चुनौती खत्म, अन्य भारतीय पहलवानों का भी संघर्ष जारी सागर ठाकरान (77 किग्रा) ने अपने क्वालीफिकेशन मुकाबले में जीत दर्ज की, लेकिन क्वार्टरफाइनल में जॉर्डन के अमरो सादेह के खिलाफ 10-0 से हार गए। सादेह ने पार टेरे (ग्राउंड) पोजीशन से चार अंकों की शानदार थ्रो लगाकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब सागर का आगे का सफर उनके प्रतिद्वंद्वी की सेमीफाइनल की जीत-हार पर निर्भर करता था। वहीं, उमेश (63 किग्रा) क्वालीफिकेशन राउंड में हार गए, जबकि नितिन (55 किग्रा) और प्रेम (130 किग्रा) भी शुरुआती दौर में बाहर हो गए। भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवानों के लिए यह प्रतियोगिता अब तक चुनौतीपूर्ण रही है।

श्रेयस ने कहा था शतक की चिंता मत करो, बस चौके-छक्के मारो - शशांक सिंह

अहमदाबाद

आईपीएल 2025 के अपने पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने मंगलवार को गुजरात टाइटंस (जीटी) को 11 रनों से हराकर धमाकेदार शुरुआत की। इस जीत में श्रेयस अय्यर की नाबाद 97 रन की पारी और शशांक सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई।

पंजाब किंग्स की पारी के अंतिम ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर 97 रन पर थे, लेकिन शशांक सिंह को निर्देश मिला कि वे हर गेंद पर चौके-छक्के लगाने की कोशिश करें। शशांक ने वैसा ही किया और अंतिम ओवर में 23 रन जोड़ते हुए टीम के स्कोर को 243/5 तक पहुंचा दिया। शशांक ने 16 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए।

मैच के बाद शशांक ने कहा, मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था, लेकिन जब पहली गेंद पर चौका लगाया तो देखा कि श्रेयस 97 पर थे। मैं उनसे पूछने जा रहा था कि क्या मुझे सिंगल लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि उनकी सेंचुरी की चिंता मत करो। यह कहना बहुत हिम्मत और टीम भावना का परिचय है।

गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 244 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे पाने के लिए उन्होंने शानदार शुरुआत की। साई सुदर्शन (74 रन), जोस बटलर और शेफर्ड रदरफोर्ड की पारियों ने टीम को 14वें ओवर तक मजबूत स्थिति में रखा। 9 से 14 ओवर के बीच गुजरात ने 87 रन बनाए, और आखिरी छह ओवरों में उन्हें 75 रन चाहिए थे।

हालांकि, पंजाब किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर विजयकुमार वैशाक ने जबरदस्त गेंदबाजी कर मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने अपने पहले दो ओवरों में केवल 10 रन दिए और 10 डॉट गेंदें फेंकी, जिससे गुजरात की लय टूट गई। पंजाब ने लगातार तीन ओवरों में कोई बाउंड्री नहीं दी, जिससे गुजरात मैच से बाहर हो गया।

शशांक ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, श्रेयस की कप्तानी सहज निर्णयों पर आधारित होती है। यही कारण है कि वह दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं। हमें पता था कि वैशाक को कब लाना है, और उसने बेहतरीन गेंदबाजी की। उसने मुश्किल ओवरों में सटीक यॉर्कर फेंके और हमें जीत दिलाई। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत की और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं।

मियामी ओपन टेनिस

मियामी में बेजारुस की आर्यानका सबालेंका चीन की झेंग क्वींविन के खिलाफ मियामी ओपन टेनिस में अंक मिलने पर उत्साहित होती हुई।

इंग्लिश क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक पल, एलिस्टेयर कुक की मैदान पर वापसी की घोषणा

लंदन

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की घोषणा कर दी है। वह जुलाई 2025 में एजबेस्टन में होने वाले ईज़मायट्रिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) में इंग्लैंड चैंपियंस टीम का हिस्सा बनेंगे। कुक, जिन्होंने 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, अब अपने पुराने साथी इयोन मोर्गन के साथ फिर से मैदान पर उतरने को तैयार हैं।

अपनी वापसी को लेकर एलिस्टेयर कुक ने एक आधिकारिक बयान में कहा, एक बार फिर अपने देश के लिए खेलना शानदार अनुभव होगा। मैं इयोन मोर्गन और बाकी खिलाड़ियों के साथ खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं।

उन्होंने इस अवसर को लेकर आभार व्यक्त करते हुए कहा, ईज़मायट्रिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स बेहतरीन क्रिकेट का अनुभव कराने का अवसर दे रही है। मैं इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हूं।

ईज़मायट्रिप डब्ल्यूसीएल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षित तोमर ने इस पर खुशी जताते हुए कहा, एलिस्टेयर कुक जैसे महान खिलाड़ी का हमारी लीग से जुड़ना टूर्नामेंट के लिए बड़ी उपलब्धि है। उनकी मौजूदगी से इंग्लैंड चैंपियंस टीम और टूर्नामेंट दोनों को जबरदस्त मजबूती मिलेगी।

इंग्लैंड चैंपियंस टीम के मालिक प्रवीण शर्मा ने कुक की वापसी को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, यह सिर्फ एक टीम घोषणा नहीं, बल्कि इतिहास रचने का पल है। कुक और मोर्गन के नेतृत्व में हमारी टीम ईज़मायट्रिप डब्ल्यूसीएल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।

वहीं टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने कुक का स्वागत करते हुए कहा, यह सिर्फ क्रिकेट की वापसी नहीं, बल्कि हमारे बीच की दोस्ती, इतिहास और नई यादें बनाने का अवसर है। हम सिर्फ खेल नहीं रहे, हम खेल को सम्मान दे रहे हैं।

ईज़मायट्रिप के अध्यक्ष और संस्थापक निशांत पिट्टी ने इस ऐतिहासिक मौके पर कहा, हम एलिस्टेयर कुक की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से बेहद उत्साहित हैं। ईज़मायट्रिप वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का उद्देश्य विश्व स्तरीय खेल आयोजनों को बढ़ावा देना है, जिससे लाखों क्रिकेट प्रशंसकों को खुशी मिले।

ईज़मायट्रिप डब्ल्यूसीएल में कुक की वापसी से इंग्लैंड चैंपियंस टीम और भी मजबूत हो गई है। 161 टेस्ट मैचों में 12,472 रन, 45.35 की औसत से 33 शतक लगाने वाले कुक को क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है।

परगट सिंह अवार्ड जीतने पर अमित रोहिदास ने कहा- यह पहचान मुझे देश के लिए और बेहतर करने की ऊर्जा देती है

नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी डिफेंडर अमित रोहिदास को हाल ही में हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में परगट सिंह अवार्ड फॉर डिफेंडर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ उन्हें 5 लाख रुपये की नकद राशि भी प्रदान की गई। इस उपलब्धि पर रोहिदास ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास पल है और यह सम्मान उन्हें टीम और देश के लिए और बेहतर करने की प्रेरणा देता है।

नामांकन मिलने के बाद की भावनाओं को साझा करते हुए रोहिदास ने हॉकी इंडिया की ओर से जारी एक बयान में कहा, मेरे अलावा इस पुरस्कार के लिए संजय, हरमनप्रीत सिंह और उदिता भी नामांकित थे और ये सभी शानदार खिलाड़ी हैं। इसलिए मैं पहले से कुछ भी नहीं कह सकता था कि कौन जीतेगा। मुझे सिर्फ नामांकन मिलने की खुशी थी। लेकिन जब मेरा नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ, तो मैं हैरान और बेहद खुश था। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था।

रोहिदास ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों से इस नामांकन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की थी, लेकिन उनके दोस्तों और शुभचिंतकों से जबरदस्त समर्थन मिला। उन्होंने कहा, मेरे कई दोस्त, खासतौर पर वे जो हॉकी नहीं खेलते, मुझे पहले से ही मैसेज कर कह रहे थे कि यह पुरस्कार मैं ही जीतूंगा लेकिन मैंने इसे किस्मत पर छोड़ दिया था। प्रतियोगिता कठिन थी, इसलिए मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस सम्मान को पाकर मैं बेहद आभारी हूं।

परगट सिंह अवार्ड जीतने के बाद अब रोहिदास नई ऊर्जा के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, यह पुरस्कार मुझे और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी इस उपलब्धि में मेरे साथी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का बड़ा योगदान है। उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। यह एक टीम प्रयास है और मैं अपने परिवार सहित सभी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा समर्थन दिया है। यह पहचान मुझे टीम और देश के लिए और बेहतर करने की ऊर्जा देती है। अपने परिवार की प्रतिक्रिया पर रोहिदास ने कहा, मेरे परिवार ने यह पुरस्कार समारोह यूट्यूब पर देखा और जब उन्हें पता चला कि मैंने यह पुरस्कार जीता है तो वे बेहद खुश थे। जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा, 'देश के लिए खेलते रहो और ऐसे ही पुरस्कार जीतते रहो।' उनकी खुशी और समर्थन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब अमित रोहिदास की नजरें आगामी टूर्नामेंट्स पर हैं, खासतौर पर एशिया कप और एफआईएच प्रो लीग पर, जो 2026 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का मौका देंगे। उन्होंने कहा, मैं हर टूर्नामेंट को एक-एक कदम आगे बढ़ने के नजरिए से देखता हूं। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान जून में होने वाली प्रो लीग और उसके बाद एशिया कप पर है।

बकरी के बच्चे के साथ योगा

आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कठिन से कठिन योगा बड़ी आसानी से कर लेते है। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। स्वीडिश की राशेल ब्रेथेन का योगा वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। राशेल ब्रेथेन अपनी बकरी पैनी लेन के साथ योगा करते इस वीडियो में नजर आ रही है। वह योगा के पोश्चर्स को अपने ऊपर इस बकरी के बच्चे साथ कर रही है। जिसमें दोनों ही जबर्दस्त बैलेंसिंग दिखा रहे हैं। राशेल को उनकी पति डेनिस ने पिछले क्रिसमस पर यह बकरी का बच्चा गिफ्ट किया था। और उसके बाद से दोनों साथ में ही योगा करते हैं। राशेल और उनके पति डेनिस दोनों ही एनिमल रेस्क्यू सेंटर भी संचालित करते हैं। इस वीडियो को अब तक फेसबुक पर 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

पायरिया क्यों होता है

मुंह में लगभग 700 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। यही बैक्टीरिया दांतों और मुंह को बीमारियों से बचाते हैं। अगर मुंह, दांत और जीभ की सफाई ठीक से न की जाए तो ये बैक्टीरिया दांतो और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। पायरिया होने पर दांतों को सपोर्ट करने वाली जबड़े की हड्डियों को नुकसान होता है। पायरिया कैल्शियम की कमी और दांत-मुंह की सफाई में कोताही बरतने से होता है।

देर से सोने वाले ज्यादा होशियार और स्मार्ट

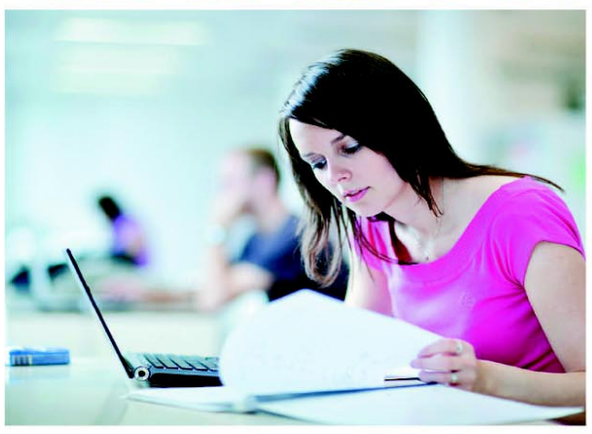

ये तो आपने जरूर सुना-पढ़ा होगा कि रात में देर से सोने पर शरीर और सेहत को बहुत नुकसान होता है लेकिन शायद ही आप जानते हों कि इसके कुछ फायदे भी हैं। अगर आप भी देर रात तक जागते हैं तो खुश हो जाइए, इसके कई फायदे हैं।

देर से सोने के फायदे

- रात में देर से सोने वाले लोग ज्यादा कलात्मक होते हैं। तब तक दिनभर की उधेड़बुन दिमाग से निकल चुकी होती हैं तो आपके दिमाग में अच्छे और क्रिएटिव विचार आते हैं।
- देर तक रात में जागने वाले ज्यादातर स्मार्ट और चालाक होते हैं।
- शोध कहते हैं कि उनका आईक्यू लेवेल ज्यादा होता है।
- यही नहीं, वे ज्यादा जिज्ञासु, बहादुर और उत्साही होते हैं। यानी वे आधी रात कोई भी डरावनी फिल्म आराम से देख सकते हैं।
- ऐसे लोग एक वक्त पर कई काम फटाफट कर लेते हैं। जाहिर है जब देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, फिर काम या स्कुल जाने में लेट होगा। गजब स्पीड में काम करते हैं फिर तो!
- ये वो लोग होते हैं जिनकी सारी पढ़ाई या काम आखिरी रात में होता है फिर भी बखूबी कर लेते हैं। डेडलाइन तो जैसे इनके लिए बच्चों का खेल है।
- रात में जागने वालों की सेक्स लाइफ भी बेहतर होती है।
- इन्हें खुद के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलता है। जब आस पास सब सो जाएंगे, तो आप अकेले जो चाहें, जैसे चाहें कर सकते हैं।
- सबसे अच्छे प्लान आधी रात एक कप कॉफी के साथ ही बनते हैं, और पूरे भी होते हैं।
- इनकी तरह 2-3 बजे तक जगने वाले दोस्त ही तो इनका सहारा होते हैं। जिन्हें जब चाहो कॉल कर सकते हैं और अपना रोना रो सकते हैं या गप्पे मार सकते हैं।

सफेद रंग के खाद्य पदार्थ खाने के फायदे

सफेद रंग के भोज्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को लिया है या जब भी ये आपकी प्लेट में रखे जाते हैं तो क्या आप इन्हें किनारे सरका देते हैं? आंकड़ों के अनुसार, लोगों की यह धारणा है कि केवल हरे भोज्य पदार्थ अच्छे होते हैं, जबकि अन्य रंगीन भोज्य पदार्थ खतरे वाले होते हैं। अपने आहार में शामिल कीजिए ये फूड हलाकि आज विज्ञान यह कहता है कि लोगों को भोजन के समय अपनी प्लेट में और रंगों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। जितने ज्यादा रंगीन भोज्य पदार्थ आपकी प्लेट में शामिल होंगे उतने ही प्रकार के पोषक पदार्थ और प्रोटीन आपके शरीर को प्राप्त होंगे। जब बात सफेद भोज्य पदार्थों की आती है तो हम सभी इन्हें ग्रहण करने में सशंकित रहते हैं। आप शायद जान गये होंगे कि हम स्वस्थ सफेद भोज्य पदार्थों की बात कर रहे हैं जिनमें अण्डे, गोभी जैसी सब्जियां तथा मुर्गे जैसे मांस शामिल हैं। स्वस्थ रहना है तो खाएं नीले रंग के आहार कैल्शियम, पोटैशियम, लौह जैसे पोषक पदार्थों युक्त इन सभी भोज्य पदार्थों के सेवन से आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

मशरूम

हफ्ते में दो बार मशरूम खाने पर स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। एक बार भोजन में मशरूम को लेने पर आपको काफी मात्रा में रेशे और कैल्शियम मिलता है। इसमें 44 कैलोरी भी होती हैं तो इसे अवश्य लें।

ओट्स

ओट्स की एक कटोरी के साथ अपने दिन की शुरूआत कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि आप चीनी की अपेक्षा शहद को चुनें। ताजे फलों को लेकर अपने भोजन को रंगीन बनाएं।

फूलगोभी

क्या आपको पता है कि फूलगोभी में स्वास्थ्यवर्धक ग्लूकोसिनेट तथा सल्फर युक्त रसायन होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं। अतः इस सब्जी को अपने भोजन में शामिल करके कैंसर को दूर रखें।

शलजम

सब्जियां हमेशा विटामिन और खनिज से भरपूर होती हैं। जब शलजम से छिलका निकाल लिया जाता है तो सफेद गूदेदार भाग को खाया जाता है जिसमें विटामिन सी, रेशे और पोटैशियम होते है और यह प्रतिरक्षण तन्त्र के लिये लाभकारी होता है।

प्याज

प्याज को किसी भी व्यंजन में डाला जा सकता है। यह न केवल व्यंजन में स्वाद बढ़ाता है बल्कि यह आपको स्वस्थ भी रखता है। प्याज में कैलोरी कम होने के साथ-साथ यह चर्बी को गलाता भी है।

अण्डे

अण्डे की सफेदी में अण्डे की आधी से ज्यादा प्रोटीन के साथ-साथ विटामिन बी 12, कम मात्रा में वसा तथा जर्दी से कम कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए अण्डे के सफेद भाग को अपने भोजन में शामिल करें।

लहसुन

लहसुन के लाभदायक गुण सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप लहसुन युक्त भोजन ग्रहण करेंगे तो आप विश्व की सबसे भयावह बिमारी कैंसर को दूर रख सकेंगे। लहसुन में पेट, आँत तथा गुदा के कैंसर के खतरों को कम करने के गुण होते हैं।

टोफू

टोफू एक और स्वास्थ्यवर्धक सफेद भोज्य पदार्थ है जिसे आपको सप्ताह में एक बार अवश्य लेना चाहिए। टोफू कैल्शियम तथा विटामिन से भरपूर होता है जो कि आपको भरपूर ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है।

गर्मियों में रामबाण है मठ्ठा

छाछ या फिर कहें मठ्ठा, गर्मियों के दिनों में अमृत के समान माना जाता है। दही से बनने वाला यह पेय काफी सारे पौष्टिक गुणों से भरा हुआ है। आयुर्वेद में तो यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति भोजन के बाद एक गिलास मठ्ठा पीता है उसे पेट से जुड़े रोग नहीं होते। अगर आपको दही खाना पसंद नहीं है तो, मठ्ठा तो जरुर पसंद आएगा क्योंकि यह स्वाद में खट्टा होता है और इसमें अगर काला नमक, जीरा और हींग आदि मसाले मिला लिए जाएं तो यह और भी चटकीला हो जाता है। गर्मी के कारण अगर पेट खराब हो गया हो तो मठ्ठे में मिश्री, काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर पीने से लाभ होता है। साथ ही इसको पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

शरीर को ठंडा करे

गर्मी की वजह से अगर तुरंत शरीर को ठंडक पहुंचानी है तो मठ्ठा पियें। यह उन महिलाओं को भी ठंडक पहुंचाता है जिन्हें मेनोपॉज के बाद गर्मी लगती है।

पाचन में मदद करे

खाने के साथ इसे लेने से पाचन अच्छा बना रहता है। साथ में यह आसानी से पच भी जाता है। इसमें यदि काली मिर्च या सेंधा नमक मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा है।

मसालेदार भोजन के बाद पेट को पहुंचाए ठंडक

तीखा और मसालेदार भोजन खाने के बाद इसे जरुर पिएं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है जो मसालों की जलन को ठंडा कर देता है। इससे एसिडिटी भी ठीक होती है।

मोटापा घटाए

तेल और मसाले वाला भोजन खाने के बाद बटर मिल्क पीने से तेल आदि का असर पेट पर नहीं पड़ता। मोटापा घटाने के लिए रोजाना मठ्ठे में सेंधा नमक मिला कर पिएं।

कैल्शियम से भरपूर

जो लोग दूध नहीं पीते उनके लिए इसमें ढेर सारा कैल्शियम भी मौजूद है, इसलिये रोजाना छाछ पीने की आदत डाल लें। ढेर सारे पौष्टिक तत्वों से भरा कैलशियम के अलावा छाछ में प्रोटीन, विटामिन बी और पोटैशियम की भी काफी मात्रा होती है। ये विटामिन और मिनरल्स आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही इसे पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।

खूबसूरती बढ़ाए

अगर बाल झड़ें तो हफ्ते में मठ्ठे से दो दिन बालों को धुलें। यदि झुर्रियां हैं तो, आटे में मठ्ठा मिला कर चेहरे पर लेप लगाएं, इससे झुर्रियां कम होने लगेंगी।

पाइल्स दूर करे

ताजा बना मठ्ठा पाईल्स के रोगियों के लिए हितकारक है। कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर इसके नियमित सेवन से कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इसमें बायो एक्टिव प्रोटीन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर के ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जाना जाता है।

भावनाओं पर नियंत्रण और व्यवहार में आता है बदलाव

दिमाग पर सीधा असर करती है यह बीमारी!

इप 2 मधुमेह के कारण क्ति अच्छा जीवन हीं जी पाता और अब धकर्ताओं ने पाया है यह मस्तिष्क की खास मताओं को भी घटा कता है। शोध के ाबिक, टाइप-2 ुमेह से मस्तिष्क की र्यप्रणाली पर बुरा असर ता है। इसमें भावनाओं नियंत्रण, व्यवहार और चार आदि शामिल हैं।

गतिविधियों को मापा...

कनाडा में वॉटरलू विश्वविद्यालय से संबद्ध शोध के मुख्य लेखक कॉरी विन्सेंट के मुताबिक, मस्तिष्क के कामकाज का यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब भी हम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत कोई काम करने का प्रयास करते हैं या हमें ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो हम पूर्ण रूप से मस्तिष्क पर निर्भर होते हैं। इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने 70 शोधों की समीक्षा की है, जिसमें टाइप 2 मधुमेह के 9,815 मरीजों की तुलना मधुमेह के अन्य 69,254 मरीजों से की गई और उनके मस्तिष्क की प्रमुख गतिविधियों को मापा गया।

कर सकते हैं बचाव...

वॉटरलू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक पीटर हॉल के मुताबिक, सामान्य रूप से टाइप-2 मधुमेह के मरीजों में दोहरी बाधाओं की वजह से मस्तिष्क गतिविधियों के नियंत्रण की अधिक जरूरत हो सकती है। संभावित रूप से ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इस बीमारी का मस्तिष्क पर असर पड़ता है। विश्व में लगभग 60.0 करोड़ लोग टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित हैं और 2030 तक ऐसे लगभग 80.0 करोड़ मामले सामने आने की संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि जिंदगी जीने के तौर-तरीके में बदलाव लाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है।

विदेशों में पढ़ाई करना हो सकता है आसान

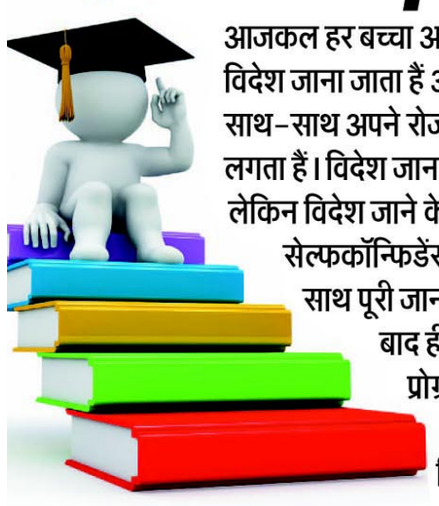

आजकल हर बच्चा अपना कॅरियर बनाने के लिए विदेश जाना जाता हैं और वहां पर पढ़ाई करने के साथ-साथ अपने रोजगार के साधन भी तलाशने लगता हैं। विदेश जाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन विदेश जाने के लिए बच्चे में सेल्फकॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ-साथ पूरी जानकारी एकत्रित करने के बाद ही विदेश में पढ़ाई करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ही विदेश में पढ़ाई करने जाएं।

इन बातों का रखें ध्यान...

- विदेश में जाने से पहले आप जिस यूनिवर्सिटी से स्टडी करना चाहते हैं पहले उसके सारे कोर्सेज की जानकारी एकत्रित कर लें, जिससे वहां पहुंचकर आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
- विदेश में जाने से पहले आप जहां ठहरने वाले हैं चाहे वो किराए का कमरा हो या हॉस्टल हो उस जगह की पूरी जानकारी एकत्रित करें। वरना आपको वहां पहुंचने के बाद समस्या हो सकती है।
- विदेश जानें से पहले आप अपनी पैकिंग सही ढंग से करें और बैंक अकाउंट खुलवाना न भूलें ऐसा करने से आपको करंसी की समस्या नहीं रहेगी और बैंक अकाउंट उसी बैंक में खुलवाएं जो विदेश पहुंचने पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाए। अन्यथा आपको ट्रांजेक्शन की समस्या से दो-चार होना पड़ सकता है।
- विदेश में पहुंचने के बाद आप अच्छे दोस्तों के साथ संपर्क में आएं और उनके साथ मेल-जोल बढ़ाएं।
- विदेश पहुंचने के बाद जाते ही नौकरी नहीं मिल जाती इसके लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ता है और वहां पहुंचकर अच्छी कंपनियों की जानकारी एकत्रित करें जो पार्ट टाइम जॉब ऑफर करती हो ऐसा करने से आप इस जॉब से पॉकेट मनी तो निकाल ही सकते हैं, जिससे आप अपने खर्च पूरे कर सकें।
- विदेश पहुंचने के बाद अगर वहां पर कोई समस्या भी आ जाए तो आप अपना सेल्फकॉफिडेंट कभी न खोएं बल्कि उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करें व ज्यादा परेशान न होकर उसका हल निकालने का प्रयास करें।

रेसिपी

भटूरा

सामग्री

2 कप मैदा, 1 1/2 टी-स्पून शक्कर, 2 टी-स्पून सूखा खमीर, 2 टेबल-स्पून दही, 1 टेबल-स्पून पिघला हुआ घी, नमक स्वादअनुसार, मैदा, बेलने के लिए, तेल, तलने के लिए

विधि

शक्कर और सूखे खमीर को 3/4 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खमीर के पिघलने तक मिला लें। ढ़क्कन से ढ़ककर 5 से 7 मिनट या मिश्रण में बुलबुले आने तक मिला लें। इस मिश्रण को मैदा, दही, घी और नमक के साथ एक साथ बाउल में मिलाकर, जरुरत हो उतने गुनगुने पानी का प्रयोग कर नरम आटा गूंथ लें। कम से म 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंथे। आटे को ढ़क्कन या गीले सूती कपड़े से ढ़ककर, फूलने के लिए लगभग 30 मिनट या आटे के हलके फूलने तक रखें। आटे को 8 बराबर भाग में बांटकर, प्रत्येक भाग को थोड़े सूखे मैदा का प्रयोग कर, 150 मिमी व्यास के गोल आकार में बेल लें। कढ़ाई में तेल गरम करें और एक-एक कर भटूरे के दोनो तरफ सूनहरा होने तक तल लें। तुरंत परोसें।

बोहरी खिचड़ी

सामग्री

ग्रेवी के लिए, 2 टेबल-स्पून घी, 1/2 कप बारीक कटे हुए प्याज, एक चुटकी गरम मसाला, 1 टी-स्पून शक्कर, नमक स्वादअनुसार, 3/4 कप फेंटा हुआ ताजा दहीं, थोड़े पानी का प्रयोग कर पीसकर मुलायम पेस्ट बनाने के लिए, 1/2 कप कटे हुए प्याज, 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, कटी हुई, 1 1/2 टी-स्पून भुना हुआ जीरा, 5 किलो सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, तोड़ी हुई, अन्य सामग्री, 3 कप पके हुए चावल, 1 1/2 कप पकी हुई तुवर दाल, नमक स्वादअनुसार, 1 कप पतले स्लाईस्ड प्याज, 2 टी-स्पून तेल, 2 टी-स्पून घी, चुपड़ने के लिए, 2 टी-स्पून दुध, परोसने के लिए

विधि

एक चौड़े नॉन-स्टिक में घी गरम करें, प्याज डालकर 2 से 3 मिनट या प्याज के पार्दर्शी होने तक भुनें। तैयार पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलायें और 1 से 2 मिनट तक भुनें। गरम मसाला, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलायें और लगातार हिलाते हुए 1 मिनट तक पकाएं। आंच से हटाकर, दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं। एक तरफ रखें। चावल, तुवर दाल और नमक को एक बाउल में अच्छी तरह मिलाएं। प्याज और तेल को एक माइक्रोवेव सुरक्षित बाउल में मिलाकर उच्च तापमान पर 4 से 5 मिनट या प्याज के करारे होने तक पका लें। एक माइक्रोवेव बेकिंग सुरक्षित बाउल को घी से अच्छी तरह से चुपड़ लें, तले हुए प्याज का आधा भाग डालें और चावल-दाल का 1/2 मिश्रण डालकर को चम्मच के पिछले भाग से अच्छी तरह फैला लें। तैयार ग्रेवी को उपर डालकर अच्छी तरह फैला लें। बचे हुए चावल-दाल के मिश्रण को डालकर अच्छी तरह फेला लें। दही के साथ तुरंत परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**